[Shri Sarada Mohanty]

Prime Minister and the Minister of State for Coal to take an early decision. Thank you, Madam.

SHRIMATI MIRA DAS (Orissa): Madam, I would like to associate myself with Mr. Mohanty. While associating with him, I urge upon the Government to start a separate coal company, exclusively for the State of Orissa immediately.

The House then adjourned for lunch at thirty-five minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-eight minutes past two of the clock, [The Vice-Chairman] **(DR. NAGEN SAIKIA) in) the Chair]**

THE PUNJAB APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1991—Contd.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): We shall now take up for consideration the Punjab Appropiation (No. 2) Bill, 1991, as moved by Shri Shantaram Potdukhe. Now, Mr. Afzal.

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मोम अफजल (उत्तर प्रदेश) : मोहतरम वाईस चेयरमैन साहब, 1991–92 के लिए सरकार की तरफ से पंजाब के लिए 7209 करोड़ रुपए का बजट मंजूरी के लिए हमारे सामने आया है। मैं समझता हूं कि जब आया है तो पास भी हो जाएगा। पिछले 6 साल से यह सिलसिला चल रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा।

इस पर मुझे एक शैर याद आ रहा है–

"फिर देखिए अंदाज़े गुलफशानिए गुफ्तार
रख दे कोई सागरो मीना मेरे हाथ में"

एक बार फिर सरकार ने इस पार्लियामेंट के सामने पंजाब का मसला रख दिया है और जो जख्म हैं उनको एक बार फिर से हरा होने का मौका मिल गया है। मोहतरम, पंजाब का जो मसला है, उसकी तफसील में जाना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। सारा मुल्क उससे बखूबी वाकिफ है। पार्लियामेंट के मुअज्जिज मेम्बरान और हमारे हाऊस के मेम्बरान जो यहां मौजूद हैं, मैं उनका वक्त कम से कम इस मसल की तफसीली बहस में ले जाकर खराब नहीं करना चाहूंगा। सिर्फ एक बात कह सकता हूं कि कुछ मांगों को लेकर यह मसला शुरू हुआ था, तवज्जह नहीं दी गई। नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता एक ऐजिटेशन शुरू हुई और उसने तशद्दुद का रुख अख्तियार कर लिया। उसके बाद आपरेशन गोल्डन टेंपल जैसा सानाहा इस मुल्क को देखना पड़ा जिसके नतीजे में मरकजी सरकार और खास तौर से कांग्रेस पार्टी पर से पंजाब के अवाम का ऐतमाद मुताजल्जल हो गया। जो हालात पंजाब में हुए मैं बकौल जावेद कंवर एक शायर हैं, उन्होंने दो मिसरों में, दो बंद इस सिलसिले म कहे हैं।

सड़कों पर सन्नाटे खेले, घर आंगन एक जेल
नेताओं ने राजनीति का ऐसा खेला खेल

बूटों की आवाज़ ने छीनी, होठों की मुसकान
एक दूजे का खून का प्यासा लगता हर इंसान

भाई का जावेद कंवर अब दुश्मन ठहरा भाई
नफरत के शैतान ने अब तो ऐसी आग लगाई

नफरत की चौपाल पै बैठा, रोए हिन्दुस्तान

एक दूजे का खून का प्यासा लगता हिन्दुस्तान।

मोहतरम, मैं साजरत के साथ कहूंगा कि जो पंजाब में माहौल पैदा हुआ उससे पंजाब के रहने वाले ऐवाम, खास तौर पर सिख बिरादरी का ऐतमाद मरकजी सरकार पर से उठकर चला गया और आज भी जो क्रेडिबिलिटी है मरकजी सरकार की वह वापस नहीं आई। ठीक है मौजूदा सरकार ने इलेक्शन का ऐलान किया है और हर तरफ से उसका स्वागत हुआ है लेकिन हमारे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिससे कि हम मरकजी सरकार की असल नीयत को भांप सकें या तोल सकें। इलेक्शन का ऐलान पहले भी हुआ था। ठीक जब ऐलान होने जा रहा था तो इलेक्शन को खत्म कर दिया गया, टाल दिया गया। अब आर्मी भेजी गई है। 80 हजार की फौज पंजाब में या तो भेजी गई है या भेजी जा रही है। 40-45 हजार पुलिस और दूसरी फोर्सज के लोग वहां पर मौजूद हैं, कई हजार होम गार्डस भी मौजूद हैं। हमें ऐसा लगता है कि जब कहीं फिरकावाराना फसाद होता है तो मैंने महसूस किया है कि लोगों की डिमांड होती है कि पी.ए.सी. को न भेजा जाए, आर्मी को भेजा जाए। यह हमारा एक ऐतमाद है आर्मी के ऊपर। लेकिन अफसोस उस वक्त होता है कि जब पंजाब में आर्मी भेजी जाए या काश्मीर में आर्मी भेजी जाए तो लोग तशवीश में मुब्तला हैं। जनाब वाइस चेयरमैन साहब, जिस वक्त आर्मी भेजने का ऐलान किया गया तो मैं आपके इल्म में यह लाना चाहता हूं कि अमरीका के अंदर कई अखबारों में एक बड़ी भयानक रिपोर्ट छपी और जबरदस्त चश्मगोइयां हुईं। वॉयस आफ अमरीका से मेरे पास एक टेलीफोन आया और उन्होंने इस तरह से मुझसे दरयाफ्त किया जैसे हमारी हुकूमत ने आर्मी न भेजी हो, मौत के हरकारे भेज दिए हों पंजाब के अंदर। जिस किस्म का प्रोपेगंडा अमरीका में हिन्दुस्तान में पंजाब में जो भी ऐक्टिवटीज होती हैं उनको लेकर किया जाता है। मोहतरम मैं पूछना चाहता हूं यहां हमारे जिम्मेदार वजीर बैठे हुए हैं कि हमारा सिफारतखाना हिन्दुस्तान पर अमरीका के अंदर इस तरह के प्रोपगंडे के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहा है। मुझे यह महसूस होता है कि अमरीका का सिफारतखाना जितना ऐक्टिव हिन्दुस्तान के अंदर है, कम से कम उससे आधा ही ऐक्टिव हमारा सिफारतखाना वहां हो जाए हम ऐसे प्रोपेगंडे का थोड़ा बहुत तोड़ कर सकते हैं। लेकिन आई.एम.एफ० के लोन और वर्ल्ड बैंक के लोन से ऐसा लगता है कि हमारी कमर इतनी बुरी तरह दब गई है कि हम अपनी इंटरनेशनल ऐक्टिविटीज को चैक भी नहीं कर सकते और कुछ तोड़ भी नहीं सकते। क्या पंजाब का मसला, क्या ईराक का मसला, क्या लीबिया का मसला। हर जगह पर एक मसकुश मुल्क दादागिरी कर रहा है, पंजाब के अंदर उसकी खुशी मदाखलत है हम कुछ कहने के लिए तयार नहीं है हम इंसानियत के नाते भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं, यह बड़े शर्म की बात है। मोहतरम, फौज भेजने में कोई बुराई नहीं है। मैं अपने मोहतरम वजीर फोतेदार साहब से कहूंगा कि कुछ तवज्जो देकर मेरी बात भी सुने (व्यवधान)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम०एल० फोतेदार) : मैं आपकी तकरीर बहुत अच्छी तरह से सुन रहा हूं।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल: मुझे खुशी है कि आप दोनों तरफ तवज्जो देते हैं। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है....

मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी (उत्तर प्रदेश) : कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना हो जाता है।

श्री एम०एल० फोतेदार : आपका दिल भी तो हमारे साथ है।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : फौज भेजने में कोई हर्ज नहीं है। एक बात कहना चाहता हूं कि फौज

[श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मोम अफजल]

भेजने से पहले हमें चाहिए कि मोहब्बत के नुमाइन्दे वहां पर भेजें। आज पांच महीने हमारी सरकार को बने हुए हो गये हैं लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि न तो अभी तक वजीरे आजम को इस बात का ख्याल आया है और न वजीरे दाखिला को इस बात का ख्याल आया है कि पंजाब जायें बजाते खुद वहां के हालात का मुशाहिदा करने के बाद कोई फैसला लें।

पंजाब के जो मौजूदा हालात हैं मैं उसके सिलसिले में सिर्फ इतना कह सकता हूं कि सिखों का एतमाद आप पर है नहीं। हिन्दू भाई खुले आम यह बात कह रहे हैं, कम से कम महसूस कर रहे हैं कि आप उन्हें सेक्योरिटी देने में नाकाम है। नतीजा यह हो रहा है कि बड़े पैमाने पर हिन्दू भाई पंजाब से माइग्रेट होकर दिल्ली और उसके आस-पास की रियासतों में आबाद हो रहे हैं। लुधियाना जो पंजाब का सबसे बड़ा सरहदी मरकज है वहां से सरमाया हैं। लुधियाना जो पंजाब का सबसे बड़ा सरहदी मरकज है वहां से सरमाया सारा ट्रांसफर हो गया है दिल्ली और दूसरे इलाकों में। इससे पंजाब की मईशत पर कितना बुरा असर पड़ेगा मुझ बताने की जरूरत नहीं है। एक तबदीली आ गई है पंजाब के अंदर।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Mr. Afzal, the time allotted to your Party is 13 minutes. There are two speakers from your Party. So, kindly keep this in view.

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मोम अफजल : मैं अभी खत्म कर रहा हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि न सिर्फ हिन्दू भाई वहां से माइग्रेट कर रहे हैं बल्कि जो वहां पर रहे हैं उनको सेक्योरिटी नहीं मिल रही है। इसकी वजह यह है कि जो पैसे वाले सिख हैं वे शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे है। जैसे कि एक जमाने में लोगों ने देहातों से शहरों की तरफ माइग्रेट किया था। यह बहुत अहम बात है। इस तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए।

करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है सदन राजपूत रहने की वजह से मैं उसकी मिसाल देता हूं कि किस तरह से कारखाने के अंदर ज्यादतियां हो रही हैं। अभी हाल ही में वहां एक जेसीटी इलेक्ट्रोनिक्स के अंदर मालिक और मजदूरों के झगड़े को लेकर हड़ताल हो गई। फैक्टरी बंद कर दी गई। वहां के वर्कर्स टेरेरिस्ट एक्टीविटी में पकड़ लिये गये। वे वर्कर्स जिन को टेरेरिस्टस एक्टीविटी में पकड़ा गया वे मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। यह एक अहम बात है कि डी.एम. और एस.एस.पी. की तरफ से अखबारों के अंदर इश्तहार साया हुए कि मजदूर काम पर वापस आ जायें वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। यह अपने में एक बड़ी नोइन्यत अजीबो गरीब मिसाल है। जो काम लेबर डिपार्टमेंट के करने का है वह डी.एम. और एस.एस.पी. कर रहे यहैं। वजह यह है कि सरमायादार तबका एडमिनिट्रेशन से मिला हुआ है। उनको ऑब्लाइज करता है। उनको गरीब मजदूरों के खिलाफ इस्तेमाल करता है। यही नहीं अभी एक मजदूर की हत्या की गई। वहां अब स्ट्राइक खत्म हो गई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिन्द मजदूर सभा के नेशनल सेक्रेटरी ए.डी. नागपाल के घर पर 6 बार रेड की गई। यह साबित करने की कोशिश की गई कि उनका ताल्लुक टेरेरिस्टों से है। पंजाब के अंदर एक अफवाह फैल गई कि जो आदमी बोलेगा उसी को टेरेरिस्ट बताया जायेगा या टेरेरिस्ट का साथी बताया जायेगा। उसको गिरफ्तार किया जायेगा या लूटा जायेगा या उसके साथ मार-पीट की जायेगी। यह करप्शन आज बराबर बढ़ता चला जा रहा है। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले यह कहना चाहता हूं कि असम, पंजाब और कश्मीर के मुतल्लिक हुकूमत के पास कोई वाजे पालिसी नहीं है। अभी कुलदीप नायर ने अपने आर्टीकल में यह दावा किया है कि केबिनेट ने इन तीन रियासतों के मुतल्लिक कोई फुलपलेज्ड बहस अपनी मीटिंग में नहीं की। यह हमारी लापरवाही की इंतहा है। आज वजीरे दाखिला और वजीरे आजम का दफ्तर उलझन

का शिकार है। फैसले कौन करेगा। सियासी लोग फैसले नहीं कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी की सतह पर फैसले किये जो रहे हैं और वक्त के मुताबिक जैसी जरूरत होती है वैसे फैसले कर लिये जाते हैं। आखिर में मैं यह बताना चाहता हूं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए। मैं कुछ तजवीज देना चाहता हूं। वजीरे दाखला 15 तारीख को पंजाब जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि पंजाब जाने से पहले पंजाब के सिलसिले में कुछ वाजे बातों का एलान होना चाहिए, कुछ वाजे, ठोस बातों का एलान होना चाहिए कि हम पंजाब के लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं यह समझता हूं कि काश्मीर और पंजाब का मसला किसी भी हालत में तब तक हल नहीं हो सकता है जब तक कि आप पाकिस्तान से इस बारे में गुफ्तगू न करें। मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर अपनी बात दोहरना चाहता हूं कि हमारे यहां कुछ लोग रोजाना यह नारा लगाते रहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाइये और पाकिस्तान में भी कुछ लोग ऐसे हैं और बिलकुल सी.आई.ए. के एजेन्ट हैं वे लोग, जो कहते हैं कि हिन्दुस्तान को सबक सिखाना चाहिए। हमने सबक 1965 और 1971 में सीख लिया है। अब हम कितने सबक एक-दूसरे को सिखा सकते हैं? मेरी गुजारिश है कि जंग करने से कोई फायदा नहीं है। अब जंग की जरूरत नहीं है। फैसले बातचीत से करने की जरूरत है, टेबल पर बैठकर बातचीत करने की जरूरत है। जब तक हम पाकिस्तान को इंवोल्व नहीं करेंगे तब तक न तो सिन्ध को मसला हल होगा, न पंजाब का मसला हल होगा और न काश्मीर का मसला हल होगा। आखिर में मैं अपने उन दोस्तों को मश्विरा देना चाहता हूं जो इस मुल्क में मोहब्बत का दावा करते हैं और आज कन्याकुमारी से लेकर काश्मीर तक रथ यात्रा के जरिये एकता का ख्वाब देख रहे हैं। मेरे नजदीक ड्राइवर नया है, लेकिन ट्रक पुराना है और काश्मीर पर निगाह है और दिल्ली पर निशाना है। इससे कोई मसला हल होने वाला नहीं है। इससे एकता नहीं होगी। मेरे ख्याल में अनेकता के ज्यादा चान्सेज हैं। उनको अपनी पालिसीज पर भी नजरसानी करनी चाहिए। मैं बड़े अदब से उन पार्टियों से भी गुजारिश करना चाहता हूं जो समझती हैं कि पंजाब और काश्मीर का ठेका हमने ले रखा है। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की हर सियासी पार्टी को और सब को मिलकर कोशिश करनी चाहिए। जो आज एकता यात्रा शुरू कर रहे हैं, अगर वे वाकई एकता चाहते हैं तो आज इस मंच से उनको दावत देता हूं कि वे तमाम सियासी पार्टियों के एक-एक आदमी को इस यात्रा में शामिल करें और मैं पहला आदमी हूंगा जो इसकी हिमायत करूंगा।

†شری محمد افضل عرف م۔ افضل (اتر پردیش):
محترم وائس چیئرمین صاحب، 1991-1992
کے لئے سرکار کی طرف سے پنجاب کے لئے
۲۰۹ کروڑ روپے کا بجٹ منظوری کے لئے
ہمارے سامنے آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں
کہ جب آیا ہے تو پاس بھی ہو جائے گا۔
پچھلے چھ سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔
اور پتہ نہیں کب تک چلے گا اس پر مجھے
ایک شعر یاد آ رہا ہے۔
"پھر دیکھئے انداز گلفشانئ گفتار
رکھدے کوئی ساغر و مینا میرے ہاتھ میں
ایک بار پھر سرکار نے اس پارلیمنٹ کے
سامنے پنجاب کا مسئلہ رکھ دیا ہے اور جو
زخم ہیں ان کو ایک بار پھر سے ہرا ہونے کا
موقع مل گیا ہے محترم۔ پنجاب کا جو مسئلہ ہے

† [] Transliteration in Arabic Script.

نفرت کی چوپال پہ بیٹھا روئے ہندوستان
اک دوجے کے خون کا پیاسا لگتا ہندوستان"

محترم میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جو پنجاب میں ماحول پیدا ہوا اس سے پنجاب کے رہنے والے عوام خاص طور پر سکھ برادری کا اعتماد مرکزی سرکار پر سے اٹھ کر چلا گیا اور آج بھی جو کریڈیبلیٹی ہے مرکزی سرکار کی وہ واپس نہیں آئی۔ ٹھیک ہے موجودہ سرکار نے الیکشن کا اعلان کیا ہے اور ہر طرف سے اس کا سواگت ہوا ہے لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جس سے کہ ہم مرکزی سرکار کی اصل نیت کو بھانپ سکیں یا تول سکیں۔ الیکشن کا اعلان پہلے بھی ہوا تھا ٹھیک جب اعلان ہونے جا رہا تھا تو الیکشن کو ختم کر دیا گیا ٹال دیا گیا۔ اب آرمی بھیجی گئی ہے۔ ۴ ہزار کی فوج پنجاب میں یا تو بھیجی گئی یا بھیجی جا رہی ہے۔ ۴۰-۴۵ ہزار پولیس اور دوسری فورسز کے لوگ وہاں پر موجود ہیں کئی ہزار ہوم گارڈس بھی موجود ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جب کہیں فرقہ وارانہ فساد ہوتا ہے تو میں نے محسوس کیا ہے کہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ پی۔ اے۔ سی کو نہ بھیجا جائے۔ آرمی کو بھیجا جائے۔ یہ ہمارا ایک اعتماد ہے آرمی کے اوپر۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب پنجاب میں آرمی بھیجی جائے یا کشمیر میں آرمی بھیجی جائے تو لوگ تشویش میں مبتلا ہیں۔

اس کی تفصیل میں جانا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ سارا ملک اس سے بخوبی واقف ہے۔ پارلیمنٹ کے معزز ممبران اور ہمارے ہاؤس کے ممبران جو یہاں موجود ہیں میں ان کا وقت کم سے کم اس مسئلے کو تفصیلی بحث میں لے جا کر خراب نہیں کرنا چاہونگا۔

صرف ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ کچھ مانگوں کو لے کر یہ مسئلہ شروع ہوا تھا۔ توجہ نہیں دی گئی۔ نتیجہ میں آہستہ آہستہ ایک ایجی ٹیشن شروع ہوئی اور اس نے تشدد کا رخ اختیار کر لیا۔ اس کے بعد آپریشن گولڈن ٹیمپل جیسا سانحہ اس ملک کو دیکھنا پڑا۔ جس کے نتیجہ میں مرکزی سرکار اور خاص طور سے کانگریسی پارٹی پر سے پنجاب کے عوام کا اعتماد متزلزل ہو گیا۔ جو حالات پنجاب میں ہوئے۔ میں بقول جاوید کمور کے جو ایک شاعر ہیں۔ انہوں نے دو مصرعوں میں دو بند۔ اس سلسلہ میں کہے ہیں۔

"سڑکوں پہ سناٹے کھیلے گھر آنگن ایک جیل
نیتاؤں نے راج نیتی کا ایسا کھیل کھیلا
بوٹوں کی آواز نے چھینی ہونٹوں کی مسکان
اک دوجے کا خون کا پیاسا لگتا ہر انسان
بھائی کا جاوید کمور اب دشمن ٹھہرا بھائی
نفرت کے شیطان نے اب تو ایسی آگ لگائی

ایکٹی وٹیز کو چیک بھی نہیں کر سکتے اور کچھ توڑ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا پنجاب کا مسئلہ کیا عراق کا مسئلہ کیا لیبیا کا مسئلہ ہر جگہ ایک مخصوص ملک داداگری کر رہا ہے۔ پنجاب کے اندر اس کی کھلی مداخلت ہے ہم کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ ہم انسانیت کے ناطے بھی بولنے کیلئے تیار نہیں ہیں۔ یہ بڑے شرم کی بات ہے۔

محترم فوج بھیجنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ میں اپنے محترم وزیر فوتیدار صاحب سے کہوں گا کہ کچھ توجہ دے کر میری بات بھی سنیں ... "مداخلت"...

شری ایم۔ ایل۔ فوتیدار ... : میں آپکی تقریر بہت اچھی طرح سُن رہا ہوں۔

شری محمد افضل عرف میم افضل : مجھے خوشی ہے کہ آپ دونوں طرف توجہ دیتے ہیں۔ میرے لیے بڑا مشکل ہے ...

مولانا عبید اللہ خان اعظمی : کہیں پر نگاہیں کہیں پر نشانہ ہو جاتا ہے۔

شری ایم۔ ایل۔ فوتیدار : آپ کا دل بھی تو ہمارے ساتھ ہے۔

شری محمد افضل عرف م افضل : فوج بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ فوج بھیجنے سے پہلے انھیں چاہیے کہ محبت کے

جناب وائس چیرمین صاحب۔ جس وقت آرمی بھیجنے کا اعلان کیا گیا تو میں آپکے علم میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کے اندر کئی اخباروں میں ایک بڑی بھیانک رپورٹ چھپی اور زبردست چرمی گوئیاں ہوئیں۔ وائس آف امریکہ سے میرے پاس ایک ٹیلیفون آیا اور انھوں نے اس طرح سے مجھ سے دریافت کیا کہ جیسے ہماری حکومت نے آرمی نہ بھیجی ہو موت کے ہرکارے بھیج دیئے ہوں پنجاب کے اندر۔ جس قسم کا پروپیگنڈہ امریکہ میں۔ ہندوستان میں۔ پنجاب میں جو بھی ایکٹی وٹیز ہوتی ہیں انکو لیکر کیا جاتا ہے۔ محترم میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں ہمارے ذمہ دار وزیر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا سفارتخانہ ہندوستان پر امریکہ کے اندر اس طرح کے پروپیگنڈہ کے خلاف کیا کارروائی کر رہا ہے۔ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ کا سفارتخانہ جتنا ایکٹیو ہندوستان کے اندر کم سے کم اس سے آدھا ہی ایکٹیو ہمارا سفارتخانہ وہاں ہو جائے تو ہم ایسے پروپیگنڈہ کا تھوڑا بہت توڑ کر سکتے ہیں۔ لیکن آئی۔ ایم۔ ایف کے لون اور ورلڈ بنک کے لون سے ایسا لگتا ہے کہ ہماری کمر اتنی بُری طرح دب گئی ہے کہ ہم اپنی انٹرنیشنل

شری محمد افضل عرف م افضل: میں ابھی ختم کر رہا ہوں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ نہ صرف ہندو بھائی وہاں سے مائگریٹ کر رہے ہیں بلکہ جو وہاں پر رہتے ہیں ان کو سیکیورٹی نہیں مل رہی ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ جو پیسے والے سکھ ہیں وہ شہروں کی طرف مائگریٹ کر رہے ہیں جیسے کہ ایک زمانے میں لوگوں نے دیہاتوں سے شہروں کی طرف مائگریٹ کیا تھا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اس طرف توجہ دی جانی چاہیے۔

کرپشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ صدر راج رہنے کی وجہ سے میں اسکی مثال دیتا ہوں کہ کس طرح سے کارخانے کے اندر زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ ابھی حال ہی میں وہاں ایک جے۔ سی۔ ٹی۔ الیکٹرونکس کے اندر مالک اور مزدوروں کے جھگڑے کو لیکر ہڑتال ہوگئی۔ فیکٹری بند کردی گئی۔ وہاں کے ورکرس ٹیرورسٹ ایکٹی ویٹیز میں پکڑ لیے گئے۔ وہ ورکرس جن کو ٹیرورسٹ ایکٹی ویٹیز کے اندر پکڑا گیا وہ مدھیہ پردیش کے رہنے والے تھے۔ یہ ایک اہم بات ہے کہ ڈی۔ ایم اور ایس۔ ایس۔ پی کی طرف سے اخباروں کے اندر اشتہار شائع ہوئے کہ مزدور کام پر واپس نمائندے وہاں پر بھیجیں۔ آج پانچ مہینہ ہماری سرکار کو بنے ہوئے ہوگئے ہیں لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نا تو ابھی وزیر اعظم کو اس بات کا خیال آیا ہے اور نہ ہی وزیر داخلہ کو اس بات کا خیال آیا ہے کہ پنجاب جائیں اور بذات خود وہاں کے حالات کا مشاہدہ کرنے کے بعد فیصلہ لیں۔ پنجاب کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے سلسلے میں میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ سکھوں کا اعتماد آپ پر رہے نہیں۔ ہندو بھائی کھلے عام یہ بات کہہ رہے ہیں یا کم سے کم محسوس کر رہے ہیں کہ آپ انھیں سیکیورٹی دینے میں ناکام ہیں۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ بڑے پیمانے پر ہندو بھائی پنجاب سے مائگریٹ ہوکر دہلی اور اس کے آس پاس کی ریاستوں میں آباد ہو رہے ہیں۔ لدھیانہ جو پنجاب کا سب سے بڑا سرحدی مرکز ہے وہاں سے سرمایہ سارا ٹرانسفر ہوگیا ہے دلی اور دوسرے علاقوں میں۔ اس سے پنجاب کی معیشت پر کتنا برا اثر پڑے گا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ایک تبدیلی آگئی ہے پنجاب کے اندر۔

ریاستوں کے متعلق کوئی فل فلیجڈ بحث اپنی میٹنگ میں نہیں کی۔ یہ ہماری لاپرواہی کی انتہا ہے۔ آج وزیراعظم اور وزیر داخلہ کا دفتر الجھن کا شکار ہے۔ فیصلے کون کریگا۔ سیاسی لوگ فیصلے نہیں کر رہے ہیں۔ بیوروکریسی کی سطح پر فیصلے کئے جا رہے ہیں۔ اور وقت کے مطابق جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسے فیصلے کر لیے جاتے ہیں۔ آخر میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے۔ میں کچھ تجاویز دینا چاہتا ہوں وزیر داخلہ ۱۵ تاریخ کو پنجاب جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب جانے سے پہلے پنجاب کے سلسلہ میں کچھ واضح باتوں کا اعلان ہونا چاہیے۔ کچھ واضح۔ ٹھوس باتوں کا اعلان ہونا چاہیے۔ کہ ہم پنجاب کے لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر اور پنجاب کا مسئلہ کسی بھی حالت میں تب تک حل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ آپ پاکستان سے اس بارے میں گفتگو نہ کریں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور میں پھر اپنی بات دہرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ روزانہ یہ نعرہ لگاتے رہتے ہیں۔ کہ پاکستان کو سبق سکھائیے۔ اور پاکستان میں بھی آجائیں ورنہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ یہ اپنے میں ایک بڑی عجیب و غریب مثال ہے۔ جو کام لیبرڈ یپارٹمنٹ کے کرنے کا ہے وہ کام ڈی۔ ایم۔ اور ایس ایس۔ پی۔ کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ سرمایہ دار طبقہ ایڈمنسٹریشن سے ملا ہوا ہے ان کو آبلائج کرتا ہے۔ ان کو غریب مزدوروں کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ یہی نہیں ابھی ایک مزدور کی ہتیا کی گئی۔ وہاں اب اسٹرائک ختم ہو گئی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہند مزدور سبھا کے نیشنل سیکریٹری اے۔ ڈی۔ ناگھال کے گھر پر بار بار ریڈ کی گئی۔ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ ان کا تعلق ٹیرورسٹوں سے ہے۔ پنجاب کے اندر ایک افواہ پھیل گئی کہ جو آدمی بولے گا اسی کو ٹیرورسٹ بتایا جائے گا۔ یا ٹیرورسٹ کا ساتھی بتایا جائے گا۔ ان کو گرفتار کیا جائے گا یا لوٹا جائے گا۔ یا اس کے ساتھ مار پیٹ کی جائے گی۔ یہ کرپشن آج برابر بڑھا چلا جا رہا ہے۔ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آسام۔ پنجاب اور کشمیر کے متعلق حکومت کے پاس کوئی واضح پالیسی نہیں ہے۔ ابھی کلدیپ نیر نے اپنے آرٹیکل میں دعویٰ کیا کہ کیبنیٹ نے ان تینوں

سے بھی گذارش کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب اور کشمیر کا ٹھیکہ ہم نے لے رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی ہر سیاسی پارٹی کو اور سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے۔ جو آج ایکتا یاترا شروع کر رہے ہیں۔ اگر وہ واقعی ایکتا چاہتے ہیں تو آج اس منچ سے میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تمام سیاسی پارٹیوں کے ایک آدمی کو اس یاترا میں شامل کریں اور میں پہلا آدمی ہوں گا جو اس کی حمایت کروں گا۔

कुछ लोग ऐसे हैं और बिल्कुल सी. आई. ए. के एजेन्ट हैं वह लोग जो कहते हैं कि हिन्दुस्तान को सबक सिखाना चाहिये। हम ने सबक १९६५ और १९७१ में सीख लिया है। हम कितने सबक एक दूसरे को सिखा सकते हैं। मेरी गुजारिश है कि जंग करने से कोई फायदा नहीं। अब जंग की जरूरत नहीं है। फैसले बात चीत से करने की जरूरत है। टेबल पर बैठ कर बात चीत करने की जरूरत है। जब तक हम पाकिस्तान को निवालो नहीं करेंगे। तब तक न तो सिन्ध का मसला हल होगा। न पंजाब का मसला हल होगा और न कश्मीर का मसला हल होगा। आखिर में मैं अपने इन दोस्तों को मशवरा देना चाहता हूं जो इस मुल्क में मुहब्बत का दावा करते हैं। और आज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक रथ यात्रा के जरिये एकता का ख्वाब देख रहे हैं। मेरे नजदीक ड्राइवर नया है लेकिन ट्रक पुराना है। और कश्मीर पर निगाह है और दिल पर निशाना है। इस से कोई मसला हल नहीं होने वाला है। इस से एकता नहीं होगी। मेरे ख्याल में एकता के ज्यादा चान्सेज हैं उन को अपनी पालिसी पर भी नजर सानी करनी चाहिये। मैं बड़े अदब से इन पार्टियों

श्री हरवेन्द्र सिंह हरपाल (पंजाब) : माननीय वाइस चेयरमैन महोदय, पंजाब के बारे में और पंजाब के एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में चर्चा हो रही है और इस बिल को हम पास करेंगे। यह एक ऐसी चीज बन गई जो लगातार चल रही है। मैं तो जब उधर बैठा था तब भी और जब इधर बैठता हूं तो तब भी, हर बार यह कहता रहा हूं कि मंत्री महोदय की तरफ से एशोरेन्स आता है कि

This is the last time. Every time they say that the Punjab budget will not be discussed here any more.

लेकिन इसका उलट होता है। चाहे पिछली सरकारें थीं या हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, सभी यही बात कहते रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो चीज पंजाब की लेजिस्लेटिव एसेम्बली में थेडबियर डिसकस होनी चाहिए ताकि लोगों को पता लग सके कि हमारे पंजाब के नुमान्दे हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं, उसके बजाय हम यह बात लोक सभा और राज्य सभा में डिसकस कर रहे हैं। यह टाइम हम किसी और काम के लिए देते तो बेहतर होता। हालांकि यह

मामला फाइनेन्स मिनिस्टर साहब का है, लेकिन अच्छा होता कि अगर यहां पर होम मिनिस्टर या मिनिस्टर आफ स्टेट होते और हमारी बातें सुनते और कुछ अमल कर पाते। मेरे से पहले अफजल साहब ने कुछ बातें कही और उनकी कुछ बातें सही थीं और कुछ बातें सही नहीं थीं। उनकी सही बातों के साथ मैं उनसे सहमत हूं। पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जिसमें देश की टोटल पोपुलेशन की दो, ढाई परसेंट पोपुलेशन रहती है और पंजाब की काश्तवाली जमीन देश की काश्तवाली जमीन का डेढ़ प्रतिशत है। लेकिन बावजूद पिछले 12–13 सालों की गैर-मुनासिब हालात के हर दफा वहां पर रिकार्ड प्रोडक्शन गेहूं और पैडी का होता है। बावजूद तरह तरह के प्रोवोकेशन के वहां पर आज तक, मैं तो इसे भगवान की ही कृपा कहूंगा कि आज तक वहां पर कम्युनल रायट्स नहीं हुए, हिन्दू-सिख फसादात नहीं हुए, चाहे कितना भी प्रोवोकेशन इटरनल रहा हो या एक्सटरनल रहा हो। इन हालातों के बावजूद लोग वहां पर नार्मल लाइफ जीना चाहते हैं। वहां के लोग अबनार्मल हालात के बावजूद देश को फूड ग्रेन का मैक्सिमम कन्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसके लिये इन लोगों को जितनी शाबासी दी जाये, जो यह खेती करके देश को अनाज देते हैं, वह कम है। लेकिन इनके साथ पूरा इंसाफ नहीं होता। मैं इस बात का जिक्र बाद में करूंगा, लेकिन इस बात में भी उनके साथ पूरा इंसाफ नहीं होता। वे देश के फूड ग्रेन के हिस्से में इतना कन्ट्रीब्यूट करते हैं लेकिन जो उनकी बेसिक जरूरियात हैं, फूड ग्रेन को पैदा करने के लिये जिन चीजों की जरूरत है उनको भी सरकार पूरे ध्यान से नहीं करती। अनाज पैदा करने के लिये पानी और बिजली की खास जरूरत रहती है। लेकिन दोनों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। जितना उनको देना चाहिये, जितना इस में पंजाब कन्ट्रीब्यूट करता है हिसाब से ध्यान नहीं दिया जाता है। कुछ पावर प्रोजक्ट्स पिछले कई सालों से पेंडिंग चले आ रहे हैं। मेरे पास कुछ फिगर्स हैं। मार्च 1992 तक वहां 773 मेगावाट की शार्टज होगी। पंजाब में जो पावर प्रोजक्ट पेंडिंग हैं, जो क्लयेर नहीं हुए, जो शुरू नहीं हुए यदि उन सब को मिला दिया जाय तो 1966–67 से ये जो प्रोजक्ट पेंडिंग हैं, आर.टी.पी. स्टेज थर्ड, सी. एन.डी.पी. स्टेज थर्ड, रजीत सागर डाम, जिसको थीम डाम भी कहा जाता है, शाहपुर कंडी एस.जी.पी. और एस. वाई. एल. एस. जी पो तो इससे 1738 मेगावाट टोटल बिजली पैदा होगी। अगर ये सारी स्कीम्स सेंक्शन कर दी जाय और सारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर दिया जाय जो उनकी स्कीम इस वक्त पेंडिंग पड़ी हुई तो भी वहां पर 26 प्रतिशत पावर की शार्टेज रहेगी। वहां की इरीगेशन की दो स्कीमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पेंडिंग पड़ी हुई है। यूटिलाइजेशन आफ सरप्लस रावी-व्यास वाटर, यह इरीगेशन के लिये बहुत जरूरी है। एक दूसरी स्कीम पड़ी हुई है एक्सटेंशन आफ नान-पैरेलियल इरीगेशन यानी यू.डी.बी.सी. प्लान, पता नहीं कब यह टेकअप होंगी? कब ये स्कीमें पास होंगी और कब इम्प्लीमेंट होंगी? आज के बाद जब ये इम्प्लीमेंट होंगी तो इनकी कास्ट क्या होगी इसका पता नहीं है। इस सिलसिले में मैं कहना चाहूंगा कि पंजाब के अंदर 14482 किलोमीटर नेटवर्क है टोटल लेंथ आफ केनाल। नाइंथ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में यह सजेस्ट किया गया है कि इन केनाल्स को मेंटेन्स करने के लिये, ताकि सही हालात में नहरें रहे, जो पुरानी नहरें हैं उनकी रिपेयर के लिये, उनको मेंटेन करने के लिये ही 54 करोड़ रुपये चाहिये। लेकिन मंत्री महोदय आपने इसमें उनको केवल 32 करोड़ रुपया दिया है जिससे कि उनकी सैलेरी भी पूरी नहीं हो जायेगी। जो इरीगेशन

3.00 P.M.

डिपार्टमेंट है, उसकी सैलेरी भी 32 करोड़ से पूरी नहीं हो पायेगी। तो आप उनका मेंटेनेंस क्या करेंगे। पानी का कितना लॉस होगा। अगर वह पानी खेतों में चला जाए किसी ढंग से आप पूरा पैसा दे दें तो बहुत उपज बढ़ सकती है और देश के अन्दर अनाज ज्यादा पैदा हो सकता है।

[श्री हरवेंद्र सिंह हंसपाल]

उपसभाध्यक्ष महोदय, आई.आर.डी.पी. एक बड़ी जरूरी स्कीम है। छोटी सी बात है। उस में फिफ्टी फिफ्टी शेयरिंग होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट ने पहले 6 करोड़ रुपया खर्च कर दिया है लेकिन आप उसके बदले 4.31 करोड़ दे रहे हैं और आपको 1.7 करोड़ अभी देना है। इस तरह से इन छोटी छोटी बातों के कारण वहां की स्कीमें रुक जाती हैं। आई.आर.डी.पी. में एक स्कीम है TRYSEM जो आई.आर.डी.पी. का बड़ा इम्पोर्टेंट कम्पोनेंट है। स्टेट गवर्नमेंट ने 60 लाख रुपया उस पर खर्च कर दिया है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपना इक्वल शेयर पच्चास प्रतिशत कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार नहीं है। मैं यह बात कह रहा था कि कंट्रीब्यूशन पंजाब के लोग कर रहे हैं और यहां से उनको शाबाशी मिलनी चाहिये, एक्सट्रा नहीं देते तो कम से कम जितना काम चलते रहने के लिए सामान चाहिये उतना भी यहां से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनको नहीं मिलता है।

अब मैं पंजाब की इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। पंजाब में आज हमारे नये गवर्नर श्री सुरेन्द्र नाथ जी कुछ महीनों से आ गये हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। हालात में सुधार हुआ है या नहीं, यह एक अलग बात है क्योंकि हालात इतने बिगड़े हुए थे। बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उनके साथी भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वहां से कुछ इंडस्ट्रीयलिस्ट्स को ले कर फाइनेंस मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी से एक मीटिंग करवाई। इडस्ट्रीज के बारे में वहां जो एक बहुत बड़ी बात चल रही है, मुझे यहां कहना चाहिये या नहीं कहना चाहिये लेकिन उसको मैं रेफर जरूर करना चाहूंगा, कुछ इस किस्म की खबरें छप जाती हैं, मैं चाहता हू कि वह खबरें सही न हों लेकिन उनका असर बहुत बुरा पड़ता है। मेरे पास इस वक्त दो तीन रेफ्रेंस हैं लेकिन मैं आपको एक ही रेफ्रेंस देता हूं। चण्डीगढ़ से छपी टाइम्स आफ इण्डिया में 27 नवम्बर को खबर छपती है,

Haryana plays host किस को ? इंडस्ट्रीज को। उसमें एक छोटा सा पैरा मैं पढ़ता हूं।

The Haryana Government has decided to develop an industrial estate in about 33 acres of land in Makdoomb village near Panipat to accomodate 300 Ludhiana-based Hosiery Textile premises. Who presided over the meeting? "These were decided in a meeting held here yesterday under the Chairmanship of the Industry Minister, Mr. Lakshmandas Aurora with the representatives of the Ludhiana Hosiery Textile Industries Association" ऐसा दूसरे मुल्कों के साथ तो हो सकता है। सिंगापुर के लोग अदन चले जाएं, हमारे यहां सिंगापुर के लोग आ जाएं लेकिन ऐसा नहीं सुना कि एक स्टेट दूसरी स्टेट के लोगों को इस तरह से माइग्रेट करने के लिए इनकरेज करे। मैं जिक्र कर रहा था फाइनेंस मिनिस्टर से उन लोगों की गवर्नर साहब ने मीटिंग करवाई। मुझे पता नहीं कि उस मीटिंग में क्या हुआ। लेकिन 1986 में आर.बी.आई. ने एक डायरेक्शन दिया कि पंजाब के हालात बहुत खराब हैं, इसलिए वहां की इंडस्ट्रीज को कुछ कनसेशन दिए जाए। मैं उन कनसेशंस की डिटेल्ज में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन वह कनसेशन लेटर एंड स्पीरिट में आज तक इम्पलीमेंट नहीं हुए। नयी इंडस्ट्रीज 1986 के बाद नहीं लगी क्योंकि वहां हालात दिन-प्रति-दिन पहले से बिगड़ते चले गये। लोग वहां से माइग्रेट करने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर नहीं भी कर रहे तो इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अगर कोई सेकेंड यूनिट लगाना है तो पंजाब के बाहर लगा रहे हैं। इसको कहते हैं फ्लाइट आफ केपिटल फ्राम पंजाब। अगर इस प्रकार की बातें होंगी तो जिसका जिक्र अभी अफजल भाई कर रहे थे बाहर बैठी हुई ताकतें पाकिस्तान जैसे लोग तो यह चाहते हैं कि वहां कुछ उधर

माइग्रेशन हो जाए और यहां से कुछ उधर माइग्रेशन हो जाएं तो उन सब के मंसूबे आराम से पूरे हो जाएंगे। आर. बी.आई. की डायरेक्शन पर कोई अमल नहीं किया गया, कोई चीज़ इम्पलीमेंट नहीं हुई। उसका कारण है आर.बी. आई. ने डायरेक्शन दे दिया, गवर्नमेंट ने यहां से कह दिया। आप जानते हैं वहां पर पंजाब नेशनल बैंक लीड बैंक है। उन्होंने अपने प्रोफिट दिखाने हैं। उन्होंने अपने पैसे को भी सेफ दिखाना है। वह चाहते हैं कि वह पैसा वहां इनवेस्ट करें जहां सेफ है, जहां सेफ रिटर्न हो। जब तक गवर्नमेंट कोई सहूलियत नहीं देगी तब तक बैंक अपना पैसा क्यों वहां इनवेस्ट करेगा? मैं पंजाब नेशनल बैंक को ब्लेम नहीं कर रहा हूं मैं इसका कर्माशियल एस्पेक्ट बता रहा हूं। डायरेक्शंस आ गई, फाइन, लेकिन वह क्यों करेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ध्यान देना पड़ेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री को ध्यान देना पड़ेगा, कोई गारंटी देनी पड़ेगी, अपनी तरफ कुछ ऑफर करना पड़ेगा। मैं यह चाहूंगा कि पंजाब के हालात 1978 से इस किस्म के चल रहे थे लेकिन 1986 से ले कर 1991 का अंत आ गया है, कुछ बातें जरूर वहां के लिए की जाएं। मैं यह नहीं कहता कि फ्री रुपया दे दिया जाए लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं कि रिडक्शन आफ मार्जिन मनी हो जाए, एग्जिस्टिंग एंड न्यू यूनिट्स की हो। 1986 में एग्जिस्टिंग के लिए किया था लेकिन वह इम्पलीमेंट नहीं हुआ। मैं यह कहता हूं कि एग्जिस्टिंग के लिए भी हो और नयी यूनिट्स के लिए मीडियम एंड लार्ज स्केल के लिए 15 परसेंट कर दिया जाए, मेरा यह सुझाव है कि टाइनी यूनिट्स के लिए 10 परसेंट कर दिया जाए। रिएलोकेशन आफ वर्किंग केपिटल किया जाए। रुपये की कीमत क्या रही है, इनपुट्स की प्राइसेज, सब चीज़ की प्राइसेज़ कहां चली गई है, यह भी आप जानते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि वर्किंग केपिटल का रिएलोकेशन होना चाहिये एडहॉक बेसेज़ पर। इसमें 50 प्रतिशत तक इनक्रीज़ करवा दीजिये। मैं माफ करने के लिए नहीं कहता लेकिन डेफरमेंट आफ टर्म लोन, वर्किंग केपिटल का एक साल के लिए दो साल के लिए जरूर कर दिया जाए। रेट आफ इंट्रेस्ट दो परसेंट नहीं तो एक या डेढ़ परसेंट पंजाब के लिए कम हो सकता है। रिशैड्यूलमेंट एंड रेगुलराइज़ेशन आफ वर्किंग केपिटल एंड टर्म लोन। एक बात बहुत जरूरी है कि जब आर.बी.आई. की तरफ से क्रेडिट स्कवीज़ लगाया जाता है तो कम से कम पंजाब में कर्माशियल बैंक्स को क्रेडिट स्वीज़ नहीं लगाना चाहिये। इससे बैंकों को एक बहुत बड़ा बहाना मिल जाता है कि क्रेडिट स्कवीज़ है, इसलिए कुछ नहीं कर सकते हैं। एट लीस्ट पंजाब में यह चीज़ अबोलिश कर देनी चाहिये। जो मैं बात कर रहा था उसके बारे में दो फिगर्ज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे वहां पर कर्माशियल बैंक्स फाइनेंस नहीं करते हैं। बैंक्स में क्रेडिट डिपोज़िट रेश्यो होता है कि उनके पास कितना पैसा जमा है और कितने प्रतिशत उसके अगेंस्ट लोगों को क्रेडिट दिया हुआ है। इसकी आल इण्डिया की फिगर्ज 58.4 प्रतिशत है अदर देन पंजाब और पंजाब में फिगर क्या है 46.8। जितनी आल इण्डिया में क्रेडिट डिपोज़िट रेश्यो है उतनी भी पंजाब में मेंटेन नहीं हो रही है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि बैंक्स यह नहीं समझते कि रुपये को यहां इनवेस्ट करना सेफ है। अगर वह इनवेस्ट करना सेफ नहीं समझते तो इंडस्ट्रीज़ की क्या हालत होगी? इंडस्ट्रीज़ बंद होंगी, इंडस्ट्रीज़ भागेंगी। हालात तो पहले ही खराब हैं। अगर वहां पर उनको कुछ सहूलियतें मिलेंगी यदि नयी इंडस्ट्रीज़ नहीं भी जाएंगी तो कम से कम वह तो चलती रहेंगी। आप सब जगह नहीं कुछ कर सकते हैं तो कम से कम तीनों जिलों में अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोज़पुर को तो कुछ एक्सट्रा दिलवाइये। अगर आप चाहते हैं कि इसी बहाने से वहां से इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएंगी लोग वहां से चले जाएंगे तो फिर मैं यह अल्फाज़ कम से कम पार्लियामेंट में इस्तेमाल करता हूं, तो फिर हम

(श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल)

उन खालिस्तानी लोगों की मदद कर रहे हैं। जब हम अपनी तरफ से रुहलियत नहीं देते तो इंडस्ट्रीज और लोग वहां से आ जाएंगे, उनके मंसूबे बड़ी खुशी से पूरे हो जाएंगे। मंत्री महोदय, इसकी तरफ आपका ध्यान देना बहुत जरूरी है। कुछ बातें मैं और कह कर अपनी बात खत्म करूंगा। ये तो मैंने थोड़ी सी बातें फाइनेंस के मुताबिक कीं। लेकिन सबसे जरूरी है कि इस वक्त पंजाब के अंदर जिसको सरकार को टाप प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, वह वहां पर रेस्टोरेशन आफ पीस है। मैं समझता हूं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इसमें कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि हमारे सेंटीमेंट्स जरूर कन्वे कर देंगे। अगर देश के अंदर हम पीस करना चाहते हैं---मंत्री महोदय, मैं बड़ी जिम्मेवारी से यह बात कह रहा हूं—और देश को अनडिवाइडेड देखना चाहते हैं तो हमें कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि पंजाब में इमीडियेटली पीस आये। मुझे खुशी है कि होम मिनिस्टर साहब ने आलरेडी यह आफर किया है कि जब भी कोई आयेगा तो वे बात करने के लिए तैयार है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं यह समझता हूं कि एक दफा बयान दे देना, कह देना काफी नहीं है। मर्ज बहुत पुराना है। नया हो तो थोड़ी दवाई देने से ठीक हो जाता है। लेकिन बहुत क्रानिक डिजीज है पंजाब की प्राब्लम। एक दफा दो दफा कहने के अलावा उनके पास आदमी भेजना पड़े, चिट्ठियां भेजनी पड़ें तो भी कोई हर्ज नहीं है।

पंजाब में इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं और बार बार कहा जा रहा है कि वहां पर इलेक्शंस जरूर करवाये जाएंगे। लेकिन मैं यह बात यहां पर कहना चाहूंगा कि पंजाब में इलेक्शंस का मैं यह तो नहीं कहता कि कोई फायदा नहीं होगा लेकिन बहुत कम फायदा होगा अगर वहां दो में से एक भी पोलिटिकल पार्टी पार्टीसिपेट नहीं करती है। पंजाब में दो पोलिटिकल पार्टीज सिर्फ रिलेवेंट हैं, एक कांग्रेस और दूसरी अकाली दल। अकाली दल कई हों, कितने हों यह अलग बात है। लेकिन इनमें से एक भी इलेक्शन में पार्टीसिपेट नहीं करती तो ऐसे इलेक्शंस का कोई लाभ नहीं होने वाला है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए और इस बात के लिए कुछ प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करने चाहिए कि अकाली दल उसमें जरूर पार्टीसिपेट करे।

इलेक्शंस की बात करते-करते एक बात का सजेश्चन और देना चाहूंगा कि वहां इलेक्शंस हों---वैसे तो मैं यह समझता हूं कि सारे देश के अंदर भी तीन हफ्ते का कैम्पेनिंग पीरियड देना कोई जरूरी नहीं है, वह क्यों नहीं है यह अलग बात है, बहुत से कारण हैं लेकिन एक सबसे बड़ा कारण यह है कि जो एक्टिव कैंडीडेट होता है उसका दो लाख रुपया रोज खर्च होता है, बेफजूल खर्च होता है। कोई फायदा नहीं होता। सारे हिंदुस्तान में जो इलेक्टोरल रिफार्म्स की बात है वह तो होती रहेगी... **(व्यवधान)**

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी (उत्तर प्रदेश) : यह डेमोक्रेटिक पार्टी है। आपकी तरह नहीं है।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : मैं जो कुछ बोल रहा हूं, पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं।

तो पंजाब के अंदर एक हफ्ते से ज्यादा कैम्पेनिंग पीरियड नहीं होना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है कैम्पेनिंग की। हमारे और के.एस. शर्मा जी के कारनामे लोगों ने बहुत देखे हैं। हमारे भी बहुत देखे हैं। इनके भी देखे हैं। सबको पता है कौन क्या है। इसलिए वहां कैम्पेनिंग की जरूरत नहीं है। एक हफ्ते की कैम्पेनिंग मोर देन सफीशियंट है। वहां बिल्कुल टाइम ज्यादा देने की जरूरत नहीं है।

वहां पर सोशियो इक्नामिक प्राब्लम की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके डिटेल में मैं इस वक्त नहीं जाऊंगा।

कोई न कोई क्रेश प्रोग्राम बने अनइम्प्लायमेंट को रिमूव करने के लिए। पंजाब के अंदर लोग फोर्सेज में जाना चाहते हैं। बहुत खुशी होती है जा करके। कारण उसके कई हैं लेकिन यह बात यहां रिकार्ड में लाना चाहूंगा कि 1980 के बाद फोर्सेज में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में और जहां रिक्रूटमेंट होता है वहां सिक्खों की गिनती कम हुई है। सिक्ख रिक्रूट्स की गिनती कम हुई है, क्यों हुई कैसे हुई इस डिटेल में मैं जा सकता हूं लेकिन इस वक्त नहीं जाउंगा। इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

हमारे भाई अफजल जी ने जो कहा, मैं उससे सहमत नहीं हूं। उन्होंने सिक्खों के लफ्ज कहे। सिक्ख पूरी तरह से सहमत नहीं हैं जो कुछ पंजाब में कुछ थोड़े बहुत मुट्ठीभर लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सिक्ख बहुत बड़ी विशाल हृदय वाली कम्युनिटी है। हमें यह एश्योर कर देना चाहिए कि हम कुछ ही कामों के साथ पूरी कम्युनिटी को कहीं एलीनिएट न कर दें। कहीं अलहिदा न कर दें। मैं सोशियो-एकोनोमिक प्रोग्राम की बात कर रहा था। उस प्रोग्राम में ऐसी चीजें न आएं जैसे रेलवे कोच फेक्टरी कपूरथला में लगी है उसका कोई लाभ पंजाब को नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? न तो पंजाब का रा मैटीरियल उसमें यूज होता है, न फिनिश प्रोडक्ट वहां बिकता है, न उसमें पंजाब के किसी आदमी की एंप्लायमेंट है। हां, एक फायदा जरूर हुआ कि जो फर्टाइल इरीगेशन वाली लैंड थी वह फैक्टरी ने सैंकड़ों एकड़ ले ली और वहां के लोग जो रोटी खाते थे उनको बेरोजगार कर दिया। पंजाब के अन्दर ऐसी फैक्टरी का कोई बिल्कुल फायदा नहीं है। हमें ऐसी इंडस्ट्री लगानी चाहिए जिससे वहां पर एम्प्लायमेंट जेनरेट हो सके।

मैं एक बात आखिरी कह कर अपनी बात खत्म करूंगा। अब तक हमारे जो एक्शंज होते हैं, मैं सारे एक्शंज तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ एक्शंज ऐसे हैं जिसमें आम लोगों का नुकसान हो जाता है और सरकार को कुछ हासिल नहीं होता और मसले भी हल नहीं होते। अगर सरकार अपनी इंटेलिजेंस को मजबूत कर ले तो मैं समझता हूं कि बहुत सा मसला हल हो जाएगा। भाई अफजल ने पाकिस्तान का जिक्र किया। पाकिस्तान के बार्डर तक मैं मि. जैकब के साथ खुद होकर आया हूं। आप हैरान होंगे कि हमारा बार्डर के ऊपर इतना इंतजाम है, जहां फेंसिंग हो चुकी है वहां पर बड़ा इलैबोरेट फैंसिंग है। बी.एस.एफ. के लोग लगे हुए हैं और हमारा वहां पर पूरा इंतजाम है। बड़ा खर्चा कर रहे हैं। करोड़ों रुपया देश का वहां खर्च हो रहा है और पाकिस्तान की तरफ वहां जंगली झाड़ियां उगी हुई हैं। मीलों-मील उधर कोई आदमी नहीं है। उसका कोई जिक्र नहीं है। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि हमें यह मसला पाकिस्तान के ऊपर टाप प्रायरिटी के साथ लेना चाहिए। उस ढंग की बात करते हैं, नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूं कुछ भी करना पड़े, मैं जंग तो नहीं कहता, कुछ भी करना पड़े, वहां पर हमें वह कर लेना चाहिए लेना चाहिए और जो रेकरिंग खर्चा वह हमें बचाना चाहिए। मैं यह बात कह रहा था कि इंटेलिजेंस को मजबूत करना चाहिए। वहां पर भी हमारी इंटेलिजेंस नहीं है बावजूद इस इंतजाम के मुझे बताया गया वहां पर कि एक डेढ़ मिनट के अन्दर उस फेंसिंग को लोग क्रास कर देते हैं। खैर, वह डिटेल अलग है। हमारी इंटेलिजेंस कहां है? डायमंड मर्चेंट्स को यहां से लोग पकड़ कर ले गए और छोड़ गए। हमारी इंटेलिजेंस कहां है? इंटलिजेंस क्या करती है? सरकार को उसे मजबूत करना चाहिए। राडू का केस है। राडू के केस में उसे उठाकर वह ले गए। बहुत बुरी बात थी। इससे बुरी बात हो नहीं सकती। लेकिन छोड़ भी गए। वहां से ट्रेन पर बैठकर आ गए, स्टेशन से टैक्सी करके घर भी आ गए। हमारी इंटेलिजेंस को पता नहीं क्या हो रहा है? या तो इंटेलिजेंस को स्क्रैप कर दीजिए। क्यों करोड़ों रुपये उस पर खर्च किए जाते हैं या फिर उसको प्रोपरली मजबूत किया जाए। उसके जो जिम्मेवार हैं उनके ऊपर

[श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल]

एक्शन लिया जाए । खैर, मेरा इस वक्त यह ताल्लुक नहीं, मैं यह कह रहा हूं कि उसको ले भी गए और छोड़ भी गए। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की आफीशियल फिगर है कि सात हजार घरों में और मेरी तो इत्तलाह है कि इससे कहीं ज्यादा घरों में उन्होंने रेड किया, लेकिन आफिशियल फिगर यह है कि 7 हजार घरों में रेड किया गया, सर्च की गई, कॉम्बिंग की गई । उससे क्या हुआ कि कम से कम वह 7 हजार जो दोस्त हैं उनको हमने दुश्मन बना लिया । वहां सिपाही गए होंगे, कोई एस०एच०ओ० गया होगा, इससे ऊपर जाने वाली बात नहीं है । क्या हुआ होगा, यह आप जानते हैं । लेकिन एक शब्द मैं कहता हूं कि उन सबको हमने दुश्मन बना लिया । फायदा क्या हुआ ? कोई फायदा नहीं हुआ । एअर इंडिया के जहाज में एक बम मिला । कैसा भी मिला, क्रूड मिला, न चलने वाला मिला, चलने वाला मिला, कुछ मिल गया । क्यों मिल गया, सैक्यूरिटी लैप्स की वजह से । अनफार्चुनेटली उस लड़के का नाम बलविन्द्र सिंह है, देखने में कलीनशेवन, लेकिन नाम उसका बलविन्द्र सिंह है । सारी सिख कम्युनिटी को बदनाम कर दिया गया । अगर हम इस किस्म की बातें करेंगे और क्यों हुआ सैक्युरिटी लैप्स ? मैं कहता हूं कि जिन्होंने सैक्युरिटी लैप्स उनको भी चौराहे पर खड़ा करके, नंगा करके, बेंत लगाए जाएं । और उनको भी कहा जाए जो पंजाब में गड़बड़ी कर रहे हैं । हमें उसमें कोई एतराज नहीं है लेकिन सवाल यह है कि कॉमन मेन को, कॉमन सिख को क्यों बदनाम किया जाता है ? मैं पूछता हूं कि कॉमन सिख का फोर्सेस में रिक्रूटमेंट क्यों कम हो गया है ? कॉमन सिख का आय०ए०एस० में रिक्रूटमेंट का परसेंटेज क्यों कम हो गया है ? कॉमन सिख का आई०पी०एस में रिक्रूटमेंट का परसेंज क्यों कम हो गया है ? क्या हर सिख टैरेरिस्ट हो गया है ? उसका कारण, चाहे वह हमारी सरकार हो, चाहे पिछली दो सरकारें हों, कारण वही है कि सरकारें इसको टॉप प्रायरिटी नहीं देती हैं । मैं कुछ और बातें करना चाहता था, लेकिन यहीं अपनी बात को खत्म करूंगा कि सरकार को प्रायरिटी देकर इस मसले को हल करना चाहिए । जैसेकि मैंने पहले कहा, गुलाम नबी आजाद साहब यहां बैठे हुए हैं, काश्मीर का मसला भी बहुत बड़ा मसला है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि काश्मीर का मसला सन् 47 से चल रहा है । तब देश की हालत खराब नहीं हुई थी । पंजाब का मसला तो 78 से शुरु हुआ है और जब पंजाब का बदतर हुआ है तो काश्मीर का बद-बदतर हो गया है ।

मैं एक अंतिम बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूं । अब वहां पर आर्मी चली गयी । वहां आर्मी जाने में कोई एतराज नहीं है । आर्मी जाए, लेकिन आप बाकी बार्डर्स भी तो सील करिए । अब हरियाणा में कोई मारा जाता है । हरियाणा में भी वही काम हो रहा है । वह अखबारों में छप गया । गवर्नमेंट ने अपनी जान बचाने के लिए कह दिया कि सिख टेररिस्ट्स ने मार दिया । अब वहां क्या हो रहा है ? उस इलाके के सिखों को उल्टा टांगकर लटकाया जा रहा है । दिन-रात यह काम हो रहा है । मेरे पास मिसालें हैं । अगर उसमें जाऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनमें से एक की जमानत मैंने करवायी है । उसके घर वाले मुझे मिलने आए थे । उन्होंने कहा कि लड़का एक महीने के बाद चारपायी से उठा है । पुलिस वालों ने उसे पहले नहीं छोड़ा । इसलिए कि उसको इतना मारा था कि अगर उसकी डाक्टरी होती, उसकी रिपोर्ट आती तो पुलिस वालों की मुसीबत हो जाती । तो हमें ऐसा करना चाहिए कि अपनी इंटेलिजेंस को मजबूत कर के जो लोग कुसूरवार हैं, जो अपराध में इनवाल्व हैं, उनके साथ सख्त-से-सख्त कार्यवाही की जाए, उसमें हमें हर्ज नहीं है । अब पंजाब के अंदर टैररिज्म शुरु हुआ तो पिछले 5–7 साल से वहां पर रेगुलर मर्डर्स होते थे, उसके बाद कोई मर्डर नहीं हुआ है क्योंकि अगर वह केस रजिस्टर किए जाएंगे तो उसकी तहकीकात करनी पड़ेगी और उसका कोई रिजल्ट निकालना पड़ेगा । अब क्या होता है ? किसी ने मार दिया तो टैररिस्ट ने ने मार दिया । लिख दिया कि टैररिस्ट

मार कर चले गए या मुकाबला हो गया। पुलिस वालों को कोई काम ही नहीं है। वहां पर करप्शन भी बहुत हो रहा है। यह बातें बहुत लंबी-चौड़ी हैं, मैं उनमें नहीं जाता, लेकिन फिर रिपीट करता हूं कि मंत्री महोदय अपनी कैबिनेट के साथियों को होम मिनिस्टर साहब को कह दीजिए कि पंजाब के मसले को टाप प्रायरिटी से हल करें। वह विजिट कर रहे हैं, लेकिन विजिट करने से कुछ नहीं होगा। आप पंजाब को चंडीगढ़ दे दें, पंजाब के पानी के मसले को हल करें, पंजाब के जमीन के मसले को हल करें। वह कहते हैं कि चंडीगढ़ देना इस वक्त इरिलेवेंट है। सवाल रेलेवेंट या इरिलेवेंट का नहीं है। चंडीगढ़ तो बना ही पंजाब के लिए था। उसके कुछ इलाके पंजाब से अलग हो गए। चाहे वह अकाली भाइयों की मेहरबानी से ही हुए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि चंडीगढ़ दूसरे को दे दिया जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब के मसले को टाप प्रायरिटी देकर हल करना चाहिए। धन्यवाद।

श्री मोहम्मद अमीन (पश्चिमी बंगाल) : सर, पंजाब के मसले पर जो बहस हो रही है, उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हर 6 महीने में यह मसला सदन में आता है और उसकी मंजूरी भी देनी पड़ती है, लेकिन मेरे ख्याल में जिन लोगों ने पंजाब के मसले का अच्छी तरह मुतालबा किया है, वह अब कुछ ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि पंजाब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है, और तमाम हालात को देखते हुए बाज लोगों के दिल में यह शक पैदा हो रहा है कि वहां से पंजाब को फिर लौटाकर वापिस लाया भी जा सकेगा या नहीं? यह शक किस लिए पैदा हो रहा है? बहुत पीछे की दास्तां सुनाने से कोई फायदा नहीं है।

यह मसला तो दस-बारह साल से उलझा हुआ है, लेकिन पांच महीना पहले जब नई सरकार बनी दिल्ली में, तो लोगों के दिल में कुछ नई उम्मीदें पैदा हुई थीं कि शायद इस मर्तबा इस मामले में संजीदगी से कार्य किया जाए और कदम उठाए जाए। पांच महीनों में सरकार ने क्या किया? अगर यह सवाल पूछा जाएं तो सिवा इसके कोई जवाब नहीं मिलता कि गवर्नर बदल दिया गया और दो एडवाइजर बदल दिए गए। पंजाब के लिए सरकार की क्या पालिसी है? यह साफ नहीं है।

वाइस चेयरमैन सर, दो बातें बहुत अच्छी तरह नजर आ रही हैं कि जब एक्सट्रीमिस्ट, इंतिहापसंद या उग्रपंथी, जो भी कहिए, वह तो एक-एक इंच मनसूबाबंद तरीके पर आगे बढ़ रहे हैं और जो वह चाहते हैं कर लेते हैं, करा लेते हैं। पंजाब का एडमिनिस्ट्रेशन उनकी मुट्ठी में है। पंजाब में जो सरकारी कारखाने हैं मरकजी हुकूमत के, उन कारखानों के मंतजमीन थर-थर कांपते हैं। वह लिस्ट दे देते हैं कि इतने लोगों को नौकरी पर रखना होगा और दूसरे दिन वे लोग रख लिए जाते हैं और जिनको वह कहते हैं कि इनको नौकरी से निकाल दो तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। मेरे ख्याल में अक्तूबर महीने में एक दिन में ही 21 नेशनलाइज्ड बैंकों को जलाया गया। कहां हैं हम लोग? पुलिस और ब्यूरोक्रेट का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ गठजोड़ कर चुका है। हमारे मंत्री साहबान वहां जाते हैं, राजभवन में बैठकर बयानात दे देते हैं और अखबारों में छप भी जाते हैं, मगर उनका कोई असर किसी पर पड़ता नहीं है। एक तरफ तो एक्सट्रीमिस्ट का यह हाल है और उनके खिलाफ कार्यवाही करने का गवर्नमेंट के पास कोई मनसूबा नहीं है। यही है हालात का सबसे बड़ा तजाद। इससे तो पंजाब का मसला हल होने वाला नहीं है।

इसका दूसरा पहलू यह है कि पंजाब के जो हिंदू कारखानेदार, ताजिर और दुकानदार हैं, वह बड़े पैमाने पर वहां से मुतकिल हो रहे हैं, सर, आप जानते हैं कि लुधियाना के आसपास हौजरी की इंडस्ट्रीज बहुत पुरानी है। इस सनद में

[श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल]

ज्यादातर हिंदू बिजनेसमेन लगे हुए हैं और इनमें तीन लाख मजदूर काम करते हैं, तीन लाख मजदूरों की रोजी चलती है। यह सारे कारखाने औने-पौने में बेचकर, अपनी जमीन बेचकर वे लोग या तो पानीपत की ओर रुख कर रहे हैं या दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे हैं । उनको धकेलने में इंतिहापसंदों का हाथ है ताकि इसका रद्दे-अमल हो अन्य रियासतों में भी और वहां से सिखों को भी निकाला जाए और वे सिख लौटकर पंजाब में चले जाए और उनको अपने मनसूबे में कामयाबी हासिल हो जाए । यह बहुत खतरनाक है । मैं इस सदन के जरिए तमाम उन लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि पंजाब के बाहर, जहां सिख हों उनकी पूरी तरह हिफाजत के ऊपर ध्यान दिया जाए और कहीं किसी ताकत को कोई शरारत करने का मौका न दिया जाए । यह इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है ।

सर, इसके अलावा पुलिस का एक हिस्सा बड़े पैमाने पर लोगों पर जुल्म ढा रहा है । वह किसी को भी गिरफ्तार करके ले जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अपने घर वालों से कहो कि पांच हजार रुपया दे जाएं, नहीं तो उग्रपंथी बोलकर के तुमको या तो जेल भेज देंगे या गोली मार देंगे । उनका यह दुख सुनने वाला कोई नहीं है । पंजाब के मासूम लोग, गरीब लोग, देहात के लोग सताए जा रहे हैं ।

यह उग्रपंथी अभी तो शहरों में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहे हैं और जब शहर उनके कब्जे में आ जाएगा तो फिर गांव की तरफ रुख करेंगे । उसके बाद एक ऐसी खतरनाक सूरते हाल पैदा होगी, जो किसी के संभाले संभालेगी नहीं । इसलिए हुकूमते-हिंद का यह फर्ज बनता है कि वह इसको किसी एक पार्टी का सवाल बनाने के बजाय इसको पूरे मुल्क के इतिहास का सवाल बनाकर देखें और जिन ताकतों से भी इस मसले को हल करने में मदद मिल सकती हो, उनके ताऊन को हासिल करें ।

सर, आप देखिए, लोंगोवाल और राजीव गांधी का एकोर्ड हुए कितना जमाना हो गया और वह एक तरफ पड़ा हुआ है । चंडीगढ़ को पंजाब के हवाले करने में क्या चीज रुकावट बनी हुई है, यह बात किसी की समझ में आती नहीं है । जो बात आप तय कर चुके हैं, उस पर अमल-दरामद नहीं हो रहा है । पानी का जो झगड़ा है उसे सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दीजिए । मुझे यकीन है कि पंजाब के लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लेंगे । 1984 में दिल्ली में जो दंगे हुए, जिसमें 3000 से ज्यादा बेगुनाह सिख मारे गए, इन रॉयट्स के जो सरगना लोग हैं वे अभी तक साफ बचे हुए हैं, उन पर कोई हाथ नहीं डाल सका है। आप सिखों के दिल में कैसे एतमाद पैदा कर सकेंगे, यह होने वाला नहीं है । अदालती कार्रवाई जरूर कुछ हो रही है, लेकिन इससे उस ज़ख्म पर मरहम नहीं पड़ रहा है जिसकी जरूरत थी । इसलिए पंजाब को अगर सुधारना है तो मुझे यकीन है कि इतने जुल्म बर्दाश्त करने के बाद भी, बहुत सारे लोग मारे गए, अक्तूबर महीने का हिसाब मैंने देखा था कि पुलिस के लोग, उनके अहल-ओ-अयाल 5, 7 या 10 आदमियों का कत्ल हो रहा है एक-एक दिन में । सियासी लोग मारे जा रहे हैं, उसमें मेरी पार्टी के लोग भी हैं, उन्होंने मुकाबला भी किया है, लड़े भी हैं, मारा भी है लोगों को लेकिन अपनी जगह छोड़कर भागे नहीं, आज भी वे अपनी जान हथेली पर रखकर के पंजाब को बचाने और पंजाब में अमन कायम करने के लिए सर-धड़ की बाजी लगाए हुए हैं । कांग्रेस के लोग भी मारे जाते हैं, दूसरी सियासी पार्टियों के लोग भी मारे जाते हैं । ये कुर्बानियां दी जिन्होंने दी हैं आज भी वे पूरी तरह मायूस नहीं हुए हैं, बशर्ते कि हुकूमत कुछ ऐसे इकदामात करे ताकि उनका इत्तिहाद बहाल हो, एतमाद को मदद मिले और वे समझें कि अब हुकूमत संजीदगी के साथ इस मसले को हल करना चाहती है । अगर यह नहीं हुआ तो फिर पानी सर से ऊंचा हो जाएगा और उसके बाद फिर कुछ किया नहीं जा सकेगा ।

इसके साथ ही एक और सवाल जुड़ा हुआ है, जिसको अगर किसी हालत में हमने नज़रअंदाज किया तो हम अपनी बर्बादी को दावत देंगे और वह है सेंटर-स्टेट रिलेशन । सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि तमाम रियासतों में जो इस वक्त बेचैनी फैली हुई है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रियासती हुकूमत, जो आवाम के करीब रहती है, उसके हाथ में कोई अख्तियार नहीं है । अख्तियार सारे दिल्ली में हैं और दिल्ली के उन अख्तियारात का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं होता है ताकि गरीब लोग, मेहनतकश लोग, मुसीबतजदा लोगों के लिए राहत का कोई सामान मुहैया हो सके । इससे बेचैनी पैदा हो रही है । अब सरकारिया कमीशन की सिफारिशात पर बातें हो रही हैं, मगर बातों से काम चलने वाला नहीं है । इसलिए मेरी ठोस तज़वीजें हैं कि "अगर पंजाब का मसला हल करना हो तो चंडीगढ़ पंजाब के हवाले कर दिया जाना चाहिए और हरियाणा को नई राजधानी बनाने के लिए जितनी रकम की जरूरत है वह उसको दी जाए ताकि हरियाणा में भी बेचैनी न हो।1984 के फसादियों को सजा दी जाए और जिनके नाम तक सरकार को मालूम हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके हाथों में हथकड़ियां डाली जाएं । पंजाबी ज़बान को पंजाब में सरकारी ज़बान का दर्जा दिया जाना चाहिए । क्या चीज़ इसमें रुकावट बनी हुई है? पंजाब में अगर पंजाबी सरकारी ज़बान नहीं बनेगी, तो कहां बनेगी ? पंजाब के आस-पास के जिन सूबों में पंजाब के लोग माकूल तादाद में रहते हों, वहां भी पंजाबी ज़बान का एहतराम किया जाना चाहिए । स्कूलों में पंजाबी के जरिए तालीम होनी चाहिए।"

ये वह इकदामात हैं, जिनसे पंजाब के लोगों के दिलों में यह अहसास पैदा होगा कि यह हमारा मुल्क है, यहां हमारी ज़बान, हमारा मज़हब, हमारी तहजीब महफूज़ है और तब वे जान की बाजी लगा देंगे ।

मरकज़ और रियासत के ताल्लुकात पर नज़रसानी करके पंजाब में चुनाव जल्द कराए जाएं । अब सरकार ने यह ऐलान तो कर दिया कि 15 फरवरी के अंदर वे वहां चुनाव कराएंगे, मगर ऐसा कुछ देखा नहीं जा रहा है जिससे यह महसूस हो कि चुनावों के लायक हालात साज़गार हो रहे हैं । वह इलेक्शन कराने से फायदा क्या जिसमें वोटर अपने हाथ से अपना वोट अपनी पसंद के मुताबिक उम्मीदवार को न डाल सकें ? इलेक्शन का ऐलान हुआ, उसके बाद धांधली हुई, बैलेट बॉक्स भरकर चले गए, वह कोई इलेक्शन नहीं है और उसके जरिए कभी नुमांइंदा सरकार पंजाब में बन नहीं सकती है ।

इसलिए एक मंसूबा बनाकर के तमाम कौमी-सियासी पार्टियों का तआवुन लेकर के पंजाब के मसले को हल करने के लिए अगर मरकजी हुकमत आगे बढ़े तो अभी भी मैं मायूस नहीं हुआ हूं और मैं समझता हूं कि पंजाब को बचाया जा सकता है, वहां अमन बहाल किया जा सकता है और हिन्दुस्तान के इतिहास को बचाया जा सकता है । शुक्रिया ।

شری محمد امین "مغربی بنگال": سر، پنجاب کے مسئلہ پر جو بحث ہو رہی ہے۔ اس کے بارے میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ۶ مہینے میں یہ مسئلہ سدن میں آتا ہے۔ اور اسکی منظوری بھی دینی پڑتی ہے۔ لیکن میرے خیال میں جن لوگوں نے پنجاب کے مسئلے کا اچھی طرح مطالعہ کیا ہے وہ اب کچھ زیادہ پریشان ہو رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ پنجاب ایک نئے موڑ پر پہنچ گیا ہے اور تمام حالات کو دیکھتے ہوئے بعض لوگوں کے دل میں یہ شک پیدا ہو رہا ہے کہ وہاں سے پنجاب کو پھر لوٹا کر واپس لایا بھی جا سکے گا یا نہیں۔ یہ شک کس لیے پیدا ہو رہا ہے بہت پیچھے کی داستان

† [ ] Transliteration in Arabic Script.

کال دیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں اکتوبر کے مہینے میں ایک دن میں ہی ۲۱ نیشلائزڈ بنکوں کو جلایا گیا۔ کہاں ہیں ہم لوگ۔ پولیس اور بیوروکریٹس کا ایک بڑا حصہ انکے ساتھ گٹھ جوڑ کر چکا ہے۔ ہمارے منتری صاحبان وہاں جاتے ہیں۔ راج بھون میں بیٹھ کر بیانات دے دیتے ہیں اور اخباروں میں چھپ بھی جاتے ہیں۔ مگر ان کا کوئی اثر کسی پر پڑتا نہیں ہے۔ ایک طرف تو ایکسٹریمسٹ کا یہ حال ہے اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کا گورنمنٹ کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ یہی ہے حالات کا سب سے بڑا تضاد۔ اس سے تو پنجاب کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔

اس کا دوسرا پہلو یہ ہے پنجاب کے جو ہندو کارخانہ دار۔ تاجر اور دکاندار ہیں وہ بڑے پیمانہ پر وہاں سے منتقل ہو رہے ہیں۔ سو آپ جانتے ہیں کہ لدھیانہ کے آس پاس ہوزری کی بہت پرانی انڈسٹری ہے۔ اس صنعت میں زیادہ تر ہندو بزنس مین لگے ہوتے ہیں اور ان میں تین لاکھ مزدور کام کرتے ہیں۔ تین لاکھ مزدوروں کی روزی چلتی ہے۔ یہ سارے کارخانے والے پونے پونے بیچ کر اپنی زمین بیچ کر وہ لوگ یا تو پانی پت کی طرف رُخ کر رہے ہیں سنانے سے کوئی فائدہ نہیں۔

یہ مسئلہ تو دس بارہ سال سے الجھا ہوا ہے۔ لیکن پانچ مہینہ پہلے جب نئی سرکار بنی دلی میں تو لوگوں کے دل میں کچھ نئی امیدیں پیدا ہوئی تھیں۔ کہ شاید اس مرتبہ اس معاملہ میں سنجیدگی سے کارروائی کیا جائے۔ اور قدم اٹھائے جائیں پانچ مہینوں میں سرکار نے کیا کیا۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے تو سوائے اس کے کوئی جواب نہیں ملتا کہ گورنر بدل دیا گیا۔ اور دو ایڈوائزر بدل دیے گئے۔ پنجاب کے لیے سرکار کی کیا پالیسی ہے۔ یہ صاف نہیں۔ وائس چیرمین سر۔ دو باتیں بہت اچھی طرح نظر آ رہی ہیں کہ جب ایکسٹریمسٹ انتہا پسند یا اگر پنتھی۔ جو بھی کہیے۔ وہ تو ایک ایک اپنے منصوبہ بند طریقہ پر آگے بڑھ رہے ہیں اور جو وہ چاہتے ہیں کر لیتے ہیں۔ کرا لیتے ہیں۔ پنجاب کا ایڈمنسٹریشن ان کی مٹھی میں ہے۔ پنجاب میں جو سرکاری کارخانہ ہیں۔ مرکزی حکومت کے۔ ان کارخانوں کے منتظمین تھر تھر کانپتے ہیں۔ وہ لسٹ دے دیتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو نوکری پر رکھنا ہوگا اور دوسرے دن وہ لوگ رکھ لئے جاتے ہیں اور جن کو وہ کہتے ہیں کہ ان کو نکال دو تو انہیں نوکری سے

ان کے قبضہ میں آجائے گا۔ تو پھر گاؤں کی طرف رُخ کریں گے۔ اس کے بعد ایک ایسی خطرناک صورتحال پیدا ہوگی جو کسی کے سنبھالے سنبھلے گی نہیں۔ اس لیے حکومت ہند کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو کسی ایک پارٹی کا سوال بنانے کے بجائے اس کو پورے ملک کے اتہاس کا سوال بنا کر دیکھیے۔ اور جن طاقتوں سے بھی اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد مل سکتی ہو۔ ان کے تعاون کو حاصل کریں۔

سر۔ آپ دیکھیے۔ لونگوال اور راجیو گاندھی کا اکارڈ ہوئے کتنا زمانہ ہوگیا ہے اور وہ ایک طرف پڑا ہوا ہے۔ چنڈی گڑھ کو پنجاب کے حوالے کرنے میں کیا چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ یہ بات کسی کی سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ جو بات آپ طے کر چکے ہیں۔ اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ پانی کا جو جھگڑا ہے۔ اسے سپریم کورٹ کے حوالے کر دیجیے۔ مجھے یقین ہے کہ پنجاب کے لوگ سپریم کورٹ کے فیصلہ کو مان لیں گے۔ ۱۹۸۴ میں دلی میں جو دنگے ہوئے۔ جس میں ۳۰۰۰ سے زیادہ بے گناہ سکھ مارے گئے۔ ان رائٹس کے جو سرغنہ لوگ ہیں۔ وہ ابھی تک صاف بچے ہوئے ہیں۔ ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکا ہے۔ آپ سکھوں کے دل میں کیسے اعتماد پیدا کریں گے اور رُخ کر رہے ہیں۔ یا اتر پردیش کی اور جا رہے ہیں۔ ان کو دھکیلنے کے لیے انتہا پسندوں کا ہاتھ ہے۔ تاکہ اس کا ردِ عمل دوسری ریاستوں میں بھی ہو اور وہاں سے سکھوں کو بھی نکالا جائے اور وہ سکھ لوٹ کو پنجاب میں چلے جائیں اور ان کو اپنے منصوبہ میں کامیابی حاصل ہو جائے۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ میں اس سدن کے ذریعہ تمام ان لوگوں سے اپیل کرتا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے باہر جہاں سکھ ہوں انکی پوری طرح حفاظت کے اوپر دھیان دیا جائے اور کہیں کسی طاقت کو شرارت کا موقع نہ دیا جائے۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔

سر۔ اس کے علاوہ پولیس کا ایک حصّہ بڑے پیمانہ پر لوگوں پر ظلم ڈھا رہا ہے۔ وہ کسی کو بھی گرفتار کر کے لے جاتے ہیں اور اسکے بعد کہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں سے کہو کہ پانچ ہزار روپیہ دے جائیں نہیں تو اگر پنتھی بول کر کے تم کو یا تو جیل بھیج دیں گے یا گولی مار دیں گے۔ ان کا یہ دُکھ سننے والا کوئی نہیں۔ پنجاب کے معصوم لوگ۔ غریب لوگ۔ دیہات کے لوگ ستائے جا رہے ہیں۔

یہ اگر پنتھی ابھی تو شہروں میں اپنے پاؤں جمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جب شہر

کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے۔ اگر یہ نہیں ہوا تو پھر پانی سر سے اونچا ہو جائیگا اور اس کے بعد پھر کچھ کیا نہیں جا سکے گا۔

اس کے ساتھ ہی ایک اور سوال جڑا ہوا ہے۔ جس کو اگر کسی حالت میں ہم نے نظر انداز کیا تو ہم اپنی بربادی کو دعوت دیں گے۔ اور وہ ہے سینٹر اسٹیٹ ریلیشن۔ صرف پنجاب میں ہی نہیں بلکہ تمام ریاستوں میں جو اس وقت بے چینی ہے پھیلی ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ریاستی حکومت جو عوام کے قریب رہتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اختیارات سارے دلّی میں ہیں۔ اور دلّی کے ان اختیارات کا استعمال اس طریقہ سے نہیں ہوتا ہے تاکہ غریب لوگ، محنت کش لوگ۔ مصیبت زدہ لوگوں کو کوئی راحت کا سامان مہیّا ہو سکے۔ اس سے بے چینی پیدا ہو رہی ہے۔ اب سرکاریہ کمیشن کی سفارشات پر باتیں ہو رہی ہیں۔ مگر صرف باتوں سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میری ٹھوس تجویزیں ہیں کہ اگر پنجاب کا مسئلہ حل کرنا ہو تو چنڈی گڑھ پنجاب کے حوالے کر دیا جانا چاہیے۔ اور ہریانہ کو نئی راجدھانی بنانے کے لیے جتنی رقم کی ضرورت ہے وہ اسکو دی جائے

پیدا کر سکیں گے۔ یہ ہونے والا نہیں ہے۔ عدالتی کارروائی ضرور کچھ ہو رہی ہے لیکن اس سے اس زخم پر مرہم نہیں پڑ رہا ہے۔ جس کی ضرورت تھی۔ اس لیے پنجاب کو اگر سدھارنا ہے تو مجھے یقین ہے کہ اتنے ظلم برداشت کرنے کے بعد بھی بہت سارے لوگ مارے گئے۔ اکتوبر مہینہ کا حساب میں نے دیکھا تھا کہ پولیس کے لوگ ان کے اہل و عیال پانچ سات یا دس آدمیوں کا قتل ہو رہا ہے۔ ایک ایک دن میں۔ سیاسی لوگ مارے جا رہے ہیں اس میں میری پارٹی کے لوگ بھی ہیں انھوں نے مقابلہ بھی کیا ہے۔ لڑے بھی ہیں۔ مارا بھی ہے لوگوں کو لیکن اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگے نہیں۔ آج بھی وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے پنجاب کو بچانے اور پنجاب میں امن قائم کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ کانگریس کے لوگ بھی مارے جاتے ہیں۔ دوسری سیاسی پارٹیوں کے لوگ بھی مارے جاتے ہیں۔ یہ قربانیاں جنہوں نے دی ہیں۔ آج بھی وہ پوری طرح مایوس نہیں ہوئے ہیں۔ بشرطیکہ حکومت کچھ ایسے اقدامات کرے تاکہ ان کا اتحاد بحال ہو۔ ان کے اعتماد کو مدد ملے کہ اور وہ سمجھیں کہ حکومت سنجیدگی

ہو رہے ہیں۔ وہ الیکشن کرانے سے فائدہ کیا جس میں ووٹر اپنے ہاتھ سے اپنا ووٹ اپنی پسند کے مطابق امیدوار کو نہ ڈال سکیں۔ الیکشن کا اعلان ہوا۔ اس کے بعد دھاندلی ہوئی۔ بیلیٹ باکس بھر کر چلے گئے۔ وہ کوئی الیکشن نہیں ہے اور اس کے ذریعے کبھی نمائندہ سرکار پنجاب میں بن نہیں سکتی ہے۔ اس لیے ایک منصوبہ بنا کر تمام قومی سیاسی پارٹیوں کا تعاون لے کر پنجاب کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگر مرکزی حکومت آگے بڑھے تو ابھی بھی میں مایوس نہیں ہوا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کو بچایا جا سکتا ہے۔ وہاں امن بحال کیا جا سکتا ہے۔ اور ہندوستان کے اتحاد کو بچایا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब विनियोग विधेयक, 1991 जिसमें पंजाब के दो करोड़ लोगों के लिये 72 अरब, 9 करोड, 50 लाख, 53 हजार रुपये का प्रावधान किया है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हू । पर उपसभाध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस की बात है कि हर साल हम इस सदन में इकट्ठे होते हैं और पजाब के इस विनियोग विधेयक को पास करने के लिये तरह-तरह की चर्चा करते हैं और मंत्री महोदय तरह-तरह के आश्वासन देते हैं, परन्तु फिर मायूस होकर अगले साल हमें यहां इकट्ठा होना पड़ता है । अच्छा यह होता क्योंकि पंजाब का

تاکہ ہریانہ میں بھی بے چینی نہ ہو۔ ۱۹۸۴ کے فسادیوں کو سزا دی جائے۔ اور جن کے نام تک سرکار کو معلوم ہیں۔ انکو گرفتار کیا جائے۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی جائیں۔ پنجابی زبان کو پنجاب میں سرکاری درجہ دیا جانا چاہیے۔ کیا چیز اس میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ پنجاب میں اگر پنجابی زبان سرکاری نہیں بنے گی تو کہاں بنے گی۔ پنجاب کے آس پاس جن صوبوں میں پنجاب کے لوگ معقول تعداد میں رہتے ہیں۔ وہاں بھی پنجابی زبان کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اسکولوں میں پنجابی کے ذریعے تعلیم ہونی چاہیے۔

یہ وہ اقدامات ہیں۔ جن سے پنجاب کے لوگوں کے دلوں میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ یہ ہمارا ملک ہے۔ یہاں ہماری زبان۔ ہمارا مذہب۔ ہماری تہذیب محفوظ ہے۔ اور تب وہ جان کی بازی لگا دیں گے۔

مرکز اور ریاست کے تعلقات پر نظر ثانی کر کے پنجاب میں چناؤ جلدی کرائے جائیں۔ اب سرکار نے یہ اعلان تو کر دیا کہ ۱۵ فروری کے اندر وہ وہاں چناؤ کرائیں گے مگر ایسا کچھ دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ جس سے یہ محسوس ہو کہ چناؤ کے لائق حالات سازگار

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

मसला दिल्ली के साथ जो जुड़ा हुआ है, वह एक ऐसा मसला है जिसको मेरे ख्याल से गृह मंत्रालय अच्छी तरह समझ सकता है । अच्छा होता गृह मंत्री भी यहां उपस्थित होते और इन कठिनाइयों को सुन सकते, इन तकलीफों को सुन सकते और एक अच्छा रास्ता निकाल सकते । अखबारों के माध्यम से पता लगा है कि गृह मंत्री पंजाब के दौरे पर जा रहे हैं । उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर यह दौरा सिर्फ राज्यपाल से मिलने के लिये या वहां के विभिन्न विभागों के सचिवों के वार्तालाप करने के लिए ही है तो मेरे ख्याल से वह पंजाब के सब अफसरों और राज्यपाल को दिल्ली बुलाकर मिल लें तो अच्छा है, क्योंकि पंजाब का नागरिक गृह मंत्री से यह अपेक्षा करता था कि गृह मंत्री पद संभालने से पहले सबसे पहले अगर कोई काम गृह मंत्री करेगा तो वह शायद कश्मीर और पंजाब के मसलों को हल करने के लिए कोई पहल ढूंढगा, कोई रास्ता ढूंढेगा, वहां पहुंचेगा, वहां के लोगों के दुख और तकलीफों को समझने की कोशिश करेगा । पर, अफसोस है कि ऐसा नहीं हो रहा है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जब भी हम पंजाब के आतंकवाद की बात करते हैं, एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं, तो मुझे यदि आता है कि पंजाब बहुत सारी चीजों में एक्सट्रीमिस्ट है । पंजाब ने जब देश के लिये कुर्बानियां दी तो वह भी एक्सट्रीम दी, जब फांसी के फंदों पर चढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने ही नारा बुलन्द किया, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के तोप के गोलों ने जब उड़ाया तो वहां सिक्ख ही खड़े थें और फांसी के रेशमी फंदों को जब चूमना शुरू किया तो उसमें भी सबसे ज्यादा संख्या पजाब की थी और जब अमरीका के सामने भारत सरकार ने हाथ पसारा और उसमें पी०एल०-480 की जगह खाने के लिये हमें गन्दी गेहूं दी, तो उस दिन सबसे ज्यादा धिक्कार अगर किसी को महसूस हुआ था तो इस देश के लिए वह पंजाबी को हुआ था और पंजाबी ने उस दिन कसम खायी थी कि हम गेहूं की इतनी पैदावार करेंगे कि हमें किसी के आगे हाथ नहीं पसारना होगा और आज वह पंजाबी आपके सामने खड़ा है और आज भी ऐसे हालातों में भी पूरे भारत को सबसे ज्यादा गेहू सबसे ज्यादा चावल, सबसे ज्यादा खाद्य पदार्थ आपको देता है, चाहे वह दूध ले लीजिए, चाहे वह मछली ले लीजिए । चाहे वह हौजरी गारमेंट्स, चाहे वह रेडीमेड गारमेंट्स ले लीजिये, हर चीज में उसने सबसे ज्यादा पैदावार करके दिखाया है कि पंजाबी इस मामले में एक्सट्रीम तक जा सकता है । जब हम छोटे-छोटे थे तो सुना करते थें कि पंजाब में कत्ल होते हैं, उनका कोई और बहाना होता है । बहाना क्या होता है? कि सिंगारा सिंह की घोड़ी अच्छी है, उस घोड़ी की दुम अच्छी है, इस पर लड़ाई हो जाती है और गर्दनें उतर जाती हैं । पता नहीं वह फिगर कहां गये? अब उस सिंगारा सिंह की घोड़ी के लिये कोई लड़ता नहीं । कैनाल के पानी पर भी लड़ाई हो जाती थीं, गर्दन उतर जाती थी, आज भी उतरती हैं, परन्तु उनका हिसाब आतंकवाद के साथ जोड़ा जाता हैं । पर उनका हिसाब आतंकवाद के साथ जोड़ा जाता है और तो और मैं देखता हूं कि पंजाब के अंदर किसी ने यह लाइन नहीं खींची कि यह हिंदू और सिख का मसला है पर पंजाब के बाहर इसको हिंदू और सिख का मसला बनाया जाता है । मैं इस सदन में पंजाब से बाहर रहने वाले सिखों की बात कह रहा हूं । पंजाब से बाहर करीब 45 लाख सिख रहते हैं और जब भी कोई ऐसी घटना घटती है तो वे दुबक जाते हैं और फिर बाल ठाकरे जैसे लोग बयान देते हैं । वे लोग इस देश में मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, रूप के नाम पर, स्वरूप के नाम पर ऐसे बयान देते हैं, जिससे लगता है कि भारत मां के बच्चों को जलवाकर ही मार डालेंगे ये लोग । ये भारत में रहते तो जरूर हैं किंतु ये भारत के दोस्त नहीं, दुश्मन हैं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, पंजाब ने सारे भारत को प्यार सिखाया । पंजाब ने सारे भारत को वेद-वेदांत दिए, धर्मग्रंथ दिए । आप रामायण उठा लें, आप वेद उठा लें, पुराण उठा लें कहां से आई यह संस्कृति ?

कहां से आई यह सभ्यता ? आज आप देखिए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कोहिमा तक, लोग पंजाबी पहनावा पसंद करते हैं, पंजाबी खान पसंद करते हैं । आज वही पंजाबियत लोगों की आंखों की किरकिरी हो गई ।

इस जलते को सही तरीके से, सही ढंग से सुधारने के लिए कोई पहल नहीं है, कोई कोशिश नहीं है और मैं इसके लिए सिर्फ सरकार को नहीं बल्कि भारतवर्ष के हरेक राजनीतिक दल को जिम्मेदार ठहराता हूं क्योंकि किसी में साहस नहीं है कि सामने आकर इस आतंकवाद का विरोध करे । किसी में साहस नहीं है कि इस जलते हुए इशु को सुलझाने की कोशिश करे, इसका समाधान निकालने की कोशिश करे ।

उपसभाध्यक्ष महोदय अगर मसला यह होता कि यहां से डिफेंस बिल पास होगा, एप्रोप्रिऐशन बिल पास होगा, तभी पंजाब की गति चलेगी तो शायद दूसरी बात होती पर मैं समझता हूं कि इस मसले को छोड़कर पंजाब पर कोई चर्चा ही नहीं होती । पंजाब का व्यापारी इस मसले पर नहीं बैठा हुआ है । यह जो पैसा आप ले जा रहे हैं, यह पैसा कहां खर्च होगा ? आपने कितने पंचायतों के घर बनाने हैं, कितना पैसा लगाना है वहां पर ? यह तो सारा ऐडमिनिस्ट्रेटिव लॉस है । यह सारा का सारा पैसा वहां की फौज और सी०आर०पी०एफ० और पुलिस के दफ्तरों में और उनके कामों में खर्च होता है । यह पैसा उनकी तनख्वाहों में बंटना है, उनकी सहूलियतों के लिये खर्च होना है । किंतु पंजाब के नागरिक के लिए आपने क्या प्रावधान किए हैं ? हो सकता है आपने उसे तरह-तरह के विभागों में बांट दिया हो—शिक्षा विभाग, उद्योग विभाग । पर पंजाब का पंजाबी आप पर डिपेंड होकर पंजाब को नहीं चला रहा है । सन 1981 से यह आग लगी हुई है । अगर 1981 का सेंसस आप देखें और आज का सेंसस देखें तो पहले जहां 45 प्रतिशत लिट्रेसी वहां थी, आज वह साढ़े 57 प्रतिशत है । स्कूल और कालेज बन्द नहीं कर सके ये आतंकवादी । पंजाब के बच्चे-बच्चियां स्कूलों और कालेजों में पढ़ने जा रहे हैं । समय पर वहां एक्जाम हो रहे हैं और वह इसलिए नहीं कि हमने उनको कोई मदद दी है तभी उनके स्कूल और कालेज चल रहे हैं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले अमरीका का बयान था कि पाकिस्तान को अब वह कह रहे हैं कि आप अब कश्मीर के और पंजाब के आतंकवादियों को ट्रेनिंग नहीं देंगे या फाइनेंस नहीं करेंगे यह अमरीका के किसी के किसी वजीर ने आकर पाकिस्तान के वजीर को कहा । मतलब यह कि सब कुछ उनकी सहमति से हो रहा था । तो यह समझा क्यों नहीं उठाते यू० एन० ओ० में यह नहीं उठता पाकिस्तान और अमरीका के साथ । आप तो मांग करते रहे कि वहां कांटे वाले तार लगाने चाहिए । मैंने तो मांग की थी कि अगर आपके यहां आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं और अगर उनको रोकना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बंद कर देते हैं ? आप आतंकवादियों को रोकना चाहते हैं जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले रहे हैं तो वह सलायत खान के नाम पर हिन्दुस्तान आ सकता है क्योंकि उसकी जुबान और नैन-नक्श हमसे बहुत मिलते जुलते हैं । आप उन्हें नहीं निकाल सकते हैं । अगर इस पार का और उस पार का पंजाबी दोनों पंजाबी बोलते हों तो आप उनमें फर्क नहीं कर सकते हैं । अगर उनको रोकना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है लेकिन इस पर क्या पहल की गई, इसका कहीं जिक्र नहीं किया गया है ।

(श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया)

उपसभाध्यक्ष महोदय, कई जगह देखा गया है कि पुलिस और आतंकवादियों और तस्करों का एक नेक्सस हो गया है । पाकिस्तान बार्डर पर हैरोइन अगर 5 लाख रुपए किलो बिकती है तो वह हैरोइन अगर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच जाए तो उसकी कीमत 35 लाख रुपए हो जाती है और वही हैरोइन अगर इंटरनेशनल ऐयरपोर्ट पर चढ़ जाए तो उसकी कीमत 1 करोड़ 35 लाख हो जाती है । यह धंधा बहुत बड़ा है, बहुत लोग, बड़े बड़े लोग इस में लगे हुए हैं । बड़े बड़े पोलिटीशियन भी इस काम में लगे हुए हैं... **(व्यवधान)**

श्रीमती विजया चक्रवर्ती (असम) : कांग्रेस के ?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : ए०जी०पी० के भी हो सकते हैं ... **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह तस्करों का, टैरोरिस्टों का और पुलिस को जो नेक्सस है यह टूटना नहीं है ! आपने कभी सुना है कि पुलिस किसी आतंकवादी को पकड़कर रिमांड पर ले जा रही हो और वह जिंदा वापिस आ जाये? आप तो हरदम सुनते हैं कि इतने आतंकवादी मारे गए और पुलिस को चोट तक नहीं लगी । पुलिस को कोई खरोंच नहीं आई और आतंकवादी मारे गए ।... **(व्यवधान)**

अगर एक ऐफिसियेंसी है पुलिस की तो उन्हें ऐवार्ड भी दिये जाते हैं । मैं नहीं कहता कि सारे पुलिस अफसर चोर हैं या बदनाम हैं या घूसखोर हैं । पर इन पुलिस अफसरों का कैटेगराइजेशन होना बहुत जरूरी है । एक पुलिस अफसर वाकई अपनी मातृभूमि की, भारत माता की रक्षा के लिए, उसकी एकता और अखंडता के लिए अपनी जान कुरबान कर देता है । लेकिन दूसरा पुलिस अफसर रुपए में अपनी भारत माता को देखता है, उसको अपनी भारत माता रुपए में नजर आती है । एक पुलिस अफसर ऐसा है जो उनकी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है । तो इन तीन तरह के पुलिस अफसरों का कैटेगराइजेशन होना बहुत जरूरी है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज हम आतंकवादियों को पकड़ कर जेल में बंद कर देते हैं । लेकिन कभी हमने उनको सुधारने की कोशिश की है ? कोई रास्ता उनको दिखाया है सुधारने का ? मंत्री जी बताने की कृपा करें कि कितने आतंकवादियों को आज तक पकड़ा गया और उनमें से कितने सुधर गए और उसके बाद उनको छोड़ा गया ? और उनको सुधारने के क्या कदम उठाए गए, क्या पहल की गई ? मेरे ख्याल में भारत सरकार के पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि ऐसी कोशिश ही नहीं है चाहे सरकार हमारी हो, चाहे वी०पी० सिंह की रही हो या चन्द्रशेखर की । हम लोगों ने पहल नहीं की है । हम लोगों ने स्टंटबाजी की है । हम लोगों ने पंजाब में उग्रवादियों को सुधारने की कोई कोशिश नहीं की है । पंजाब के नौजवान की शान है उसकी वर्दी । पंजाब में या तो वह लहलहाते हुए खेतों में काम करना चाहता है या फिर वह मिलिटरी कलर की वर्दी पहन कर हाथ में बंदूक लेकर भारतमाता की सेवा करना चाहता है । पर पंजाबी युवकों से यह अधिकार भी छीन लिया गया । हिन्दुस्तान की आर्मी में जो पंजाबी नौजवान भर्ती होता था उसकी संख्या घटा दी गई । मुझे आज तक इसका कारण नहीं मालूम हुआ कि क्यों घटा दी गई । क्या भारतमाता को शूरवीरों की जरूरत नहीं है ? क्या भारतमाता को अपने जवानों-परवानों की जरूरत नहीं है ? क्या भारतमाता ने कहीं इन्कार किया है कि मुझे सिख नौजवान नहीं चाहिए ? क्या भारतमाता कहती है कि सिख नौजवान मेरी रक्षा नहीं करता ? क्या भारतमाता कहती है कि सिख गद्दार हो गये हैं ? यह मेरा सवाल है । इन सवालों का जवाब सिर्फ एक तरफ जाता है कि उन नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती । उन नौजवानों का गौरव वापस लौटा दीजिए तो पंजाब में शांति खुद वापस आ जायेगी । पंजाब के उन सिख नौजवानों का गौरव वापस कर दीजिए जो आंखों में आंसू लिये हुए हैं ताकि वे मिलिटरी की वर्दी पहन कर हाथों में बंदूक लेकर इस देश के दुश्मनों को सरहदों पर खड़ा करके उनको बेनकाब

कर सके । यह गौरव वापस लौटा दीजिए। आज तक जो आंदोलन चल रहा है उसमें कुछ नौजवान विभ्रांत हो सकते हैं । अगर वे गलत काम करते हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो कड़ाई से कदम उठाइये । पर जब इस कड़ाई के नाम पर यह देखने को आता है कि फिरोजपुर में एक परिवार के 8 सदस्य जिनकी उम्र 85 से लेकर 2 साल तक थी बीच बाजार में सरेआम खड़ा करके गोली से उड़ा दिया गया और गोली से उड़ाया किसने ? अगर कोई आतंकवादी उड़ाता तो मैं सोचता पर उनको उड़ाने वाले हमारे रक्षक सी० आर०पी०एफ० के जवान थे । इन आठ लोगों को मारने से हम दूसरी तरफ 8 हजार आतंकवादी पैदा करते हैं । हम उन्हें मौका देते हैं कि नौजवान भड़कें । हम नौजवानों को नौकरी नहीं देते । हम नौजवानों को रास्ता नहीं देते । हम नौजवानों को सुधार करने का कोई प्रोग्राम नहीं देते । उधर गांवों में बूढ़ों से लेकर बच्चों तक को निहत्थों को गोली मार कर उड़ा देते हैं । पुलिस की वर्दी में जब मारने जाता है तो उन्हें भड़कने का मौका मिलता है । देश के बाहर जो ताकतें बैठी हैं उन्हें भी भड़कने का मौका मिलता है । वह यह कहते हैं कि यह देश है तुम्हारा जो तुम्हारे अपने भाई-बहनों से ऐसा सलूक करता है। क्यों नहीं कोर्ट-मार्शल होता है इनका ? आपने कानून तो बनाया है कि कोई भी आतंकवादी पकड़ा जाता है तो उसको नेशनल सेक्योरिटी एक्ट और दूसरे एक्ट में बंद कर देंगे । फिर जब ऐसे पुलिस अफसर पकड़े जाते हैं रंगे हाथों तो उन पर कौन सा कानून लागू होता है ? क्यों नहीं एक्शन होता उन पर ? बहुत शर्म आती है उस वक्त जिस वक्त हम इस सदन में बैठकर यह सोचते हैं कि पुलिस को और वहां के गवर्नर को सारे अधिकार दे दिये जायें । इस सदन से दिये हुए अधिकारों का जब दुरुपयोग होता है तो बड़ी शर्म आती है । मैं आपके माध्यम से सरकार से फिर मांग करता हूं कि अगर पंजाब में शांति लानी है तो पंजाबियों के दिल में जो शंका है कि शायद दिल्ली वाले चुनाव नहीं कराना चाहते तो इस शंका को दूर करें। और उनके दिल में विश्वास पैदा करें । गृह मंत्री महोदय अगर पंजाब जा रहे हैं तो सिर्फ सरकारी अफसरों से ही मुलाकात न करें कम से कम उन परिवारों से भी मिल कर आयें जिन पर आतंकवादियों के जुल्म हुए हैं । जिनकी मां-बहिनों को सरेआम बेइज्जत किया गया है, जिनके बच्चे उनकी मांओं की कोखों से छीन कर गोली से उड़ा दिये गये हैं । उन परिवारों से भी मिलें जिनके परिवारों के ऊपर पुलिस के जुल्म हुए हैं और बेकसूर लोगों की हत्यायें की गई हैं । तभी शायद कोई फैसला होगा । अगर आप उनको दिलासा दिला देंगे कि भारत सरकार बलिष्ठ रूप में खड़ी होकर उनकी रक्षा करेगी तो शायद उस दिन उनके मन में विश्वास जागेगा और उस दिन शायद इस सदन के मन में भी विश्वास जागेगा कि पंजाब की समस्या का समाधान हो रहा है, अन्यथा नहीं ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Hon. Members, I have to announce that the Minister of State for Railways Shri Mallikarjun, is going to make a *suo motu* statement at 5 p.m. today regarding the accident involving Train No. 3 Pathankot-Baijnath passenger train between Jawanwala Shahr-Harsar Dehri on Pathankot-Joginder Nagar narrow gauge section of Northern Railway on 7-12-1991.

श्री कृष्ण लाल शर्मा (हिमाचल प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, पंजाब के बारे में वर्ष 1991–92 के विनियोग बिल पर आज चर्चा हो रही है और हम सब जानते हैं कि यह बिल पास होगा । इसमें अड़चन आने वाली नहीं है । मुझे जरा एक बात की तरफ अपनी सरकार का और मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना है । हम बार-बार यह चर्चा करते हैं कि पंजाब को कोई न कोई पैकेज देने वाले हैं । अच्छा होता कि इसी विनियोग बिल 1991–92 पर चर्चा के दौरान हम कोई पकेज, कंक्रीट और ठोस पकेज को एनाउन्स करते कि पंजाब उद्योगपतियों

[श्री कृष्ण लाल शर्मा]

के लिए, कृषकों के लिए, वहां पर रोजगार के लिए या शांति और व्यवस्था के लिए, तीन-चार चीजों को लेकर कोई पैकेज बनाते और उस पैकेज के लिए खर्चा करने का प्रावधान करते हैं । यह पैकेज भी आप इस में जोड़ते तो अच्छा होता। आप चुनाव की भी चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह विनियोग बिल 1991–92 शायद आखिरी होगा और चुनावों के बाद यह विधान सभा में जाएगा । इस पैकेज का न होना, यह मैं एक लैप्स मानता हूं । हमारे पंजाब की जो कहानी है उसमें तीन बातों को ध्यान में लाना है । मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार के पास पंजाब की कोई स्थायी नीति नहीं है । केन्द्रीय सरकार चाहे जो भी रही हो; उन्होंने कोई स्थायी नीति नहीं बनाई । सरकार ने समय पर कोई एक्शन नहीं लिया । कार्यवाही तब की जब पानी सिर से ऊपर चला गया । एक बात और है और बड़ी अफसोसनाक है कि सरकार ने जितने भी वचन दिये, जितने भी निर्णय किये, एग्रीमेंट किये, जितने भी जुडिसियल या दूसरे निर्णय हुए और जितने भी वायदे किये गये उनमें से एक भी आज तक पूरा नहीं हुआ। सारे वायदे, सारी बातें, पंजाब में अनइम्प्लीमेंटेड रहीं, धरी की धरी रह गई । ये ऐसी चीजें हैं जिनसे इरीटेशन पैदा होना स्वाभाविक है । मेरा एक सीधा-सा प्रश्न है और वह प्रश्न यह है कि क्या इस सरकार ने सचमुच में आतंक को प्राथमिकता दी है? अभी-अभी कुछ दिन पहले मैंने एक प्रश्न गृह मंत्री जी से पूछा था तो उन्होंने नक्सलवाद पर जौयन्ट कमान्ड और कोआर्डिनेशन कमेटी की बात की थी। लेकिन मैंने पूरक प्रश्न पूछा था कि क्या आतंकवाद के लिए कोई कोआर्डिनेशन कमेटी है तो गृह मंत्री जी ने बताया कि आतंकवाद के कोई कोआर्डिनेशन कमेटी आज तक नहीं बनाई गई है । 1978 से यहां पर आतंकवाद चल रहा है । पंजाब में है, काश्मीर में है, असाम में है, तमिलनाड़ में है और अन्य कई प्रदेशों में है । लेकिन गृह मंत्रालय के स्तर पर या किसी भी स्तर पर कोई कोआर्डिनेशन कमेटी नहीं है जो आतंकवाद को डील करे । इस सरकार की कौन-सी प्राथमिकता है, आज किस प्रकार की बात हो रही है? रायट्स फोर्स बनाने की बात हो रही है । बहुत अच्छी बात है । आज बात होती है, नक्सलवाद को डील करने के लिए जौयन्ट कमान्ड और कोआर्डिनेशन कमेटी बने ।

4 P.M.

लेकिन आतंकवाद के लिये कोई भी इस तरह की चर्चा नहीं है । इसका मतलब यह है कि यह विषय हमारे सामने प्राथमिकता में नहीं है और हम पंजाब तथा कश्मीर में जो आतंकवाद है उसको ऐसे ही चलाना चाहते हैं और इसके लिये कोई बात ठीक ढंग से नहीं करना चाहते हैं । गलत फैसले किये जाते हैं, मैं एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर यह बात कहना चाहता हूं । मुझे उस समय दुख हुआ जिस समय 22 जून को वहां चुनाव स्थगित किये गये और सेना को वापस बुलाया गया । अब सेना भेजी गई है दुबारा । मैं यह पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार में कौन आदमी बैठा है जो यह डेट का फैसला करता है । कौन करता है यह समय का चयन ? वहां पर सेना भेजी गयी उस दिन जिस दिन गुरु नानकदेव का जन्म दिन था । यह समाचार आप अखबारों में पढ़िये कि गुरु नानक देव के जन्म दिन पर पंजाब में सेना भेजने का निर्णय । यह निर्णय दो-चार दिन आगे पीछे भी हो सकता था। इसी तरह से लोगों के दिलों में घाव पैदा हुए हैं। ब्लूस्टार आपरेशन भी गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिन पर किया गया था । क्या ये दिन चुनने का तरीका है ? क्या इस तरह से लोगों के दिलों में, उनके हृदयों में चोट पहुंचाना चाहते हैं जो इस तरह से निर्णय लेते हैं? मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि पंजाब से सेना को चुनाव के स्थगन होने के बाद जो वापस बुलाया गया था तो क्या वहां की हालत अच्छी हो गई थी या 22 जून के बाद ही पुलिस वालों की फैमिलीज को मारने की प्रथा शुरू हुई? आज जब मैं यहां पर खड़ा होकर बोल रहा हूं तो मेरे मन में बड़ा दुख है । हमारे एक सीनियर साथी, पंजाब के नेता श्री राम

प्रकाश प्रभाकर जिनका दो दिन पहले अपहरण किया गया था, बटाला से घर जाते हुए, आज खबर है कि उनको आतंकवादियों ने मार दिया है, उनकी हत्या कर दी है । डा० बल्देव प्रकाश जी इस समय पंजाब में एकता के प्रतीक हैं, उनके ऊपर हमला हुआ लेकिन कभी गृह मंत्री या किसी केंद्र के मंत्री को इतनी फुरसत नहीं है कि वहां जाकर उनके दुख-दर्द में शामिल हो जाएं। किसी भी सीनियर एक्टीविस्ट, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, उसके दुखदर्द में शामिल होने के लिये इस सरकार के किसी भी नेता और किसी भी मंत्री को फुरसत नहीं है, कोई भी उनके पास जाने के लिये तैयार नहीं है मैं यह कहना चाहता हूं कि शायद यह सरकार हृदयहीन हो गयी है । जितने भी निर्णय लिये जाते हैं वे दलगत बातों को ध्यान में रखकर किये जाते हैं, वे चुनाव को सामने रखकर किये जाते हैं । सेना को भेजा जायेगा चुनाव कराने के लिये, निर्दोष लोगों की रक्षा के लिये नहीं । चुनाव कराने के लिये सेना भेजी जायेगी । यह देखिये कि कितना कन्ट्राडिक्शन है कि सेना भेजी जा रही है, 15 फरवरी को चुनाव होंगे और फिर उसके बाद चंडीगढ़ को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया गया है, पंजाब के कई अन्य जिलों को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जा रहा है । यह जो किया जा रहा है, क्या यह स्थिति चुनाव के अनुकूल है या प्रतिकूल है ? मेरा यह कहना है कि 15 फरवरी को कोई पवित्र तिथि नहीं है । अगर आज तक सरकार ने अपने सारे वायदे पूरे किए होते तो मैं कहता कि यह सरकार अपनी बात की धनी है और वह इसे 15 फरवरी के कायदे को भी पूरा कर देगी । लेकिन 15 फरवरी को कोई पवित्र तिथि नहीं है । पंजाब में चुनाव कराने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की आवश्यकता है । इसके लिए यह एक प्री-कंडीशन है, सरकार इसको पहले पूरा करे और फ्री एंड फेयर इलैक्शन के लिए वातावरण बनाए । अभी 11 मई तक काफी समय है । हम चुनाव के पक्ष में हैं, हम चुनाव के विरोध में नहीं हैं । हम चाहते हैं कि चुनाव हों । लेकिन चुनाव कराने के लिए वहां पर अनुकूल वातावरण बनाने की जरूरत है । इस भय और आतंक के वातावरण में, जब कि सरकार ही खुद कुछ एरियाज को डिस्टर्ब्ड एरिया डेक्लेयर करती जा रही है तो ऐसी हालत में वहां चुनाव कराकर पंजाब के साथ न्याय नहीं होगा ।

एक और बात है, पिछला चुनाव, चाहे आप लाख आर्ग्युमेंट दे दें, पिछला चुनाव इसलिए स्थगित हुआ था क्योंकि आप दुबारा चुनाव में आना चाहते थे । उस समय आप चुनाव में नहीं थे, इसलिए चुनाव में भाग लेने के लिए आपने उस समय चुनाव स्थगित कराया । अब सब अकाली कह रहे हैं और मैं श्री हंसपाल जी की बात से मैं सहमत हूं, उन्होंने कहा कि पंजाब में अगर अकाली चुनाव में नहीं आयेंगे तो पंजाब के चुनाव मीनिंगलैस हो जायेंगे । आज अकाली घोषणा कर रहे हैं कि वे चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे तो क्या ऐसी स्थिति में भी वहां चुनाव कराए जायेंगे ? सरकार यह स्पष्ट करे कि अगर अकालियों की कोई भी पार्टी चुनावों में हिस्सा नहीं लेगी तो क्या फिर भी वहां चुनाव कराए जायेंगे, जबर्दस्ती करायें जायेंगे ? क्या इससे पंजाब को फायदा होगा ? सरकार इस संबंध में अपनी नीति स्पष्ट करे । सरकार वहां पर ऐसा माहौल बनाए जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा पार्टियां चुनावों में हिस्सा ले सकें और उनके अंदर यह विश्वास पैदा हो कि अगर हम चुनाव में हिस्सा लेंगे तो उसका फायदा होगा । महोदय, पंजाब की स्थिति अब कोई दलगत राजनीतिक स्वार्थों की सीमा के अंदर नहीं रह गई है बल्कि यह उससे परे निकल गयी है । इसलिए इसमें सभी पार्टियों को विश्वास में लेना जरूरी है । सभी दलों को विश्वास में लेकर पंजाब में चुनाव की तिथि तय होनी चाहिए । यह नहीं कि कोई एक पार्टी तय कर दे और फिर आप कांसेसस बनाएं इस तरह से काम नहीं चलेगा ।

सभी पार्टियों को विश्वास में लिया जाए और कोशिश की जाए कि अकाली भी जरूर आयें और इस तरह का माहौल

[श्री कृष्ण लाल शर्मा]

बनाया जाए जिसमें चुनाव हों, और सब लोग फिर डैमोक्रेटिक प्रोसेस को शुरू करने के लिए शामिल हो सके । पंजाब के बारे में जब भी हम सोचते हैं, हम सोचने के लिए और विचार करने के लिए इकट्ठा होते हैं तो उस में एक सवाल यह भी आता है कि सरकार ने किस किस मोड़ पर कितनी बडी गलतियां की हैं । 1966 में पंजाब और हरियाणा अलग राज्य बने, तब से चंडीगढ़ का मसला पड़ा हुआ है । 1973 में इंदिरा गांधी अवार्ड दिया गया उसका क्या हुआ ? उसके बाद 1985 में लोंगोवाल राजीव समझोता हुआ, उसका क्या हश्र हुआ । उसके बाद कितने आयोग बनाए, पानी के सवाल पर, सीमा के सवाल पर, सारे आयोगों ने अपनी रिपोर्ट दी, उनका क्या हश्र हुआ? एक भी प्वांइट का इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ । पंजाब के बारे में एक भी समझौते को इम्पलीमेंट नहीं किया गया है । हम यह कैसे समझ लें कि सरकार पंजाब समस्या के हल के लिए गंभीर है? 22 जून का चुनाव स्थगित करना एक हिमालयन ब्लंडर था वैसा माहौल दोबारा नहीं मिलेगा सरकार को चुनाव करना है तो वैसा माहौल बनाना चाहिए । श्री मोहम्मद अफजल ने हमारी एकता यात्रा के बारे में चर्चा की । मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूं कि हम ने सभी पोलिटिकल पार्टीज को पार्लियामेंट के अंदर और बाहर निमंत्रण दिया है और उनको कहा है कि 26 जनवरी को हम श्रीनगर में झण्डा फहराना चाहते हैं वह सब उस में शामिल हों, वहां उनका स्वागत होगा, मैं मोहम्मद अफजल साहब का भी स्वागत करूंगा, वह भी आ जायें, उनका स्वागत होगा (व्यवधान)

श्री शब्बीर अहमद सलारिया (जम्मू और कश्मीर): 26 जनवरी को झण्डा फहराने का ढकोसला कर रहे हैं (व्यवधान) वहां पर जो झण्डे लगे हुए हैं (व्यवधान) सेक्रेटेरियेट पर झण्डा लहरा रहा है, गवर्नर हाउस पर लहरा रहा है (व्यवधान) एजूकेशन इंस्टीट्यूशंस पर झण्डे लहारा रहे हैं, पहले उन झण्डों को उतारिए । हिन्दुस्तान के आवाम को रथ यात्रा से उन्होंने खून की होली में नहला दिया था (व्यवधान) यह वही लोग हैं जो झण्डा लहराने का ढकोसला कर रहे हैं (व्यवधान) हिन्दुस्तान गुरुवत और रोटी के मसले टुड़(व्यवधान) यह ढकोसला आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए वोटों के लिए है (व्यवधान)

†شری شبیر احمد سلاریہ: ۲۶ جنوری کو جھنڈا پھرانے کا ڈھکوسلا کر رہے ہیں "مداخلت" ہاں پر جو جھنڈے لگے ہوئے ہیں "مداخلت" سیکریٹریٹ پر جھنڈا لہرا رہا ہے گورنر ہاؤس پر لہرا رہا ہے "مداخلت" ایجوکیشنل انسٹی ٹیوٹ پر جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ پہلے ان جھنڈوں کو اتاریے۔ ہندوستان کے عوام کو رتھ یاترا سے انہوں نے خون کی ہولی میں نہلا دیا تھا۔ "مداخلت" یہ وہی لوگ ہیں جو جھنڈا لہرانے کا ڈھکوسلا کر رہے ہیں "مداخلت" ہندوستان میں غربت اور روٹی کے مسئلے ہیں۔ "مداخلت" یہ ڈھکوسلا عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ووٹوں کیلئے ہے "مداخلت"

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Kindly sit down, Mr. Salaria. Please do not drag other subjects into the debate... (*Interruptions*). Mr. Sharma, please confine yourself to the subject of the debate only.

श्री शब्बीर अहमद सलारिया : यह सब आप आवाम के वोट हासिल करने के लिए कर रहे हैं (व्यवधान) पहले जो झंडे लहरा रहे हैं उनको उतारिए (व्यवधान) फिर अपना यह ढकोसला करिए (व्यवधान)

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

شری شبیر احمد سلاریہ : یہ سب آپ عوام سے ووٹ حاصل کرنے کیلئے کر رہے ہیں۔ "مداخلت" پہلے جو جھنڈا لہرا رہے ہیں انکو "مداخلت" پھر اپنا یہ ڈھکوسلا کریئے "مداخلت"

श्री कृष्ण लाल शर्मा : मैं कहता हूं कि 26 जनवरी को अगर कोई झण्डा फहराए तो उसका स्वागत होना चाहिए, हम सब को आमन्त्रित कर रहे हैं, इसका विरोध नहीं करना चाहिए । हम सब को आमन्त्रित कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ पंजाब की स्थिति पर मैंने अपनी बात कही और इसके लिए आपने मुझे जो समय दिया, आपको धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Now, Mr. Ratnakar Pandey. Mr. Pandey, your time is very short. You have only five minutes because the time allotted to your party is 55 minutes.

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, थोड़ा समय दीजिए, मैं नहीं चाहता था कि भारत यात्रा की चर्चा होती लेकिन हमारे सदन के माननीय सदस्य श्री कृष्ण लाल शर्मा जी ने उसे छेड़ दिया है पंजाब विनियोग विधेयक के संदर्भ में, इसलिए मैं उसी से शुरू करूंगा । अभी इनके दल के अध्यक्ष श्री मुरली मनोहर जोशी जी का रविवार के हिन्दुस्तान टाइम्स में एक साक्षात्कार छपा है जिसमें उन्होंने यह साफ कहा है कि—

"Muslims are Hindus because they live in Hindustan. If you call yourself an Indian, you are calling yourself a Hindu.. It was customary in those days for the victor to inflict an insulton the vanquished. Hence the temple at Ayodhya was destroyed and a mosque like structure was imposed. It was a hopeless structure."

सारे देश के राजनीतिक दलों को आमन्त्रित कर रहे हैं कि भारत यात्रा में शामिल हो जाएं। यह राष्ट्र के ध्वज की जगह केसरिया ध्वज को अपना राष्ट्रीय ध्वज मानते हैं और इनके सारे कार्यक्रम और नीतियां ओवरसीज बी. जे. पी. ने बनाई हैं। इनके लोकसभा के नेता माननीय आडवाणी जी जब दौरे पर चलते हैं उनके साथ भारत के पत्रकार नहीं रहते हैं बल्कि विदेशी पत्रकार ज्यादा रहते हैं। जैसे गृह मंत्री जी ने बराबर इस सदन में दोहराया है कि सुपर पावर्ज का आतंक मचाने में, उनको आमन्त्रित करने में, जब-जब यह राष्ट्र टूटा है तब तब इस देश में ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने विदेशियों को यहां आमन्त्रित किया है, उनकी गुलामी की है, उनके कदमों में सजदा किया है। यही कारण है कि ओवरसीज बी.जे.पी. बना कर के जो लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं, साम्प्रदायिकता की आग भड़के हिन्दू, मुसलमान और सिख में नफरत पैदा कर के, इस देश के टुकड़े-टेकड़े करना चाहते हैं क्योंकि इन का अस्तित्व उन सुपर पावर्ज के हाथों में बिका हुआ है। यह मैं सदन में रिकार्ड कराना चाहता हूं। पंजाब विनियोग बिल जो आया है मैं कहना चाहता हूं कि अभी कहा गया रोजगार, कृषि, शान्ति व्यवस्था पर कोई पेकेज देते। मुझे यह नहीं लगता कि माननीय कृष्ण लाल शर्मा जी ने इस बिल को पढ़ा है क्योंकि उस में जितने भी बिन्दु हो सकते हैं शासन से संबंधित उनका ब्यौरेवार विवरण दिया गया है। जितनी चीजों की ओर ध्यान उन्होंने दिलाया है सब मदों में रुपया रखा गया है। हमें कहते हैं कि सरकार की कोई स्थाई नीति नहीं है। आंख में धूल झोंकना बन्द करो, अफवाहें फैलाना बन्द करो। अगर हमारी सरकार की स्थाई नीति नहीं है तो हमने क्यों डंके की चोट पर डेमोक्रेसी रिस्टोर कराने के लिए, पंजाब में चुनाव कराने के लिए घोषणा की है? क्यों हमारे गृह मंत्री जी 15 दिसम्बर को पंजाब जा रहे हैं?

वहां जा कर के सारी स्थिति की स्टडी करेंगे कि सरकार क्या करे जिससे चुनाव और शान्ति व्यवस्था बहाल हो।

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

सरकार ने जो वचन दिया है, उसे सरकार ने पूरा नहीं किया, सरकार की सूची में आतंकवाद प्राथमिकता में है या नहीं, सरकार दलगत निर्णय करती है, सरकार हृदयहीन है, सेना चुनाव के लिए भेजी जाएगी, 15 फरवरी को चुनाव स्थगित कर दिया जाए, अनुकूल वातावरण नहीं है, कांग्रेस चुनाव में दोबारा सत्ता में आना चाहती है, पंजाब में अकाली चुनाव में भाग लेंगे या नहीं चुनाव अकालियों के बिना होगा, चण्डीगढ़ के मसले का क्या होगा। यह हमारे पूर्व वक्ता माननीय कृष्ण लाल शर्मा जी के भाषण का जिस्ट था। इन सब का मैं एकदम घोर विरोध करता हूं। इनकी पीच पोलिटिकली मोटिवेटेड है। मैं बताना चाहता हूं कि पंजाब समस्या के समाधान के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद बागडोर अपने हाथ में ले ली है। पंजाब राज्य की स्थिति पर रोजाना जो रिपोर्ट मिलती है, वह फाइनली प्रतिदिन प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री जी के साथ बैठ कर स्वयं हल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने तीन सूत्री फार्मूले को इस्तेमाल करने का प्रायः मन बना लिया है और उस पर काम भी कर रहे हैं। एक तो है फौज की तैनाती, दूसरा चुनाव तथा नवोदित पंजाब समझौता कुछ मालूम नहीं है, खाली क्रिटीसाइज करते हैं, क्रिटीसाइज करते जा रहे हैं। जब से सरकार बनी है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन तीन मुद्दों पर काफी गम्भीरता से काम करना आरम्भ कर दिया है और उसी का यह परिणाम है कि हम पंजाब में चुनाव में भाग लेने जा रहे हैं। हमारी सरकार चुनाव कराने के लिए है। यह सदन ऊब चुका है, कितनी बार अब तक यहां विनियोग विधेयक आया है, कितने प्रधानमंत्री हुए, कितने नहीं रहे, बार बार आता है और बार बार सरकारों को यहां कुछ कहना पड़ता है लेकिन वह नहीं करती हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी इस सदन को आश्वासन देंगे कि पंजाब का यह अन्तिम विनियोग विधेयक होगा। इसके बाद वहां जब डेमोक्रेसी आप रेस्टोर कर देंगे तो वहां की असेम्बली अपने आप इस चीज को करेगी और इस पर हमको पंजाब की बागडोर अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोनों सदनों को। उस फारमूले पर अमल करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। फौज तैनात हो गयी है। अब चुनाव की तैयारी हो रही है। हमारे गृह मंत्री जी इस देश के बड़े ही रिस्पांसिबुल लोगों में माने जाते हैं उनसे मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि वन्स फार आल इस बार चुनाव होने ही चाहिएं और उसके लिए कांग्रेस दल के कार्यकर्ता के रूप में हम अपनी सेवाएं अर्पित करने को तैयार हैं चाहे हमारी लाश लौटे लेकिन हम डेमोक्रेसी वहां रेस्टोर करेंगे। उसमें अब कहीं कोई समझौता नहीं होना चाहिए। न एक कदम हमको पीछे हटाना है श्री राजीव गांधी जी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में लंडन के पहल कहा था कि हम पंजाब में डमोक्रेसी रेस्टोर करेंगे और उसको हमारी सरकार कर रही है लेकिन आज भी आप अविश्वास कर रहे हैं। फौज की तैनाती हमने की। हम चन्द्रशेखर की सरकार और वी०पी० सिंह की सरकार नहीं हैं। दुशाला ओढ़कर कई करोड़ रुपया अपनी सुरक्षा पर सादा वर्दी में खर्च करके दो फर्लांग तक जोप में चलकर नाटक रचाने वाले भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह पंजाब की समस्या को बरबाद करने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार आदमी है। उसके बाद चन्द्रशेखर जी का शुरू से ही रुख रहा आतंकवादियों को प्रश्रय देने का। उठाकर देखिए उनके स्टेटमेंट्स को, हमेशा उन्होंने पंजाब में... (व्यवधान)

SHRI MENTAY PADMANABHAM (Andhra Pradesh): You were giving shelter to Mr. Chandra Shekhar.

DR. RATNAKAR PANDEY: That was wrong. We should not have supported. We have given the Prime Ministership, and got the dead body of our former Prime Minister. We have done wrong.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Please carry on.

DR. RATNAKAR PANDEY: The election was held. And this thing has occurred.

और हुआ वह।

फौज की तैनाती से जो खाड़कू हैं उनके ठिकाने बदल गये हैं और अब वे तेजी के साथ—अभी जैसे उत्तर प्रदेश की तराई में घटना हुई—हर जगह देश में

व्याप्त हो रहे हैं । पांच छः हजार खाड़कू और वे कौन हैं । दोतीन बार इधर मुझे पंजाब और चंडीगढ़ जाने का मौका मिला है, पिछले महीने में भी मिला और इस महीने भी । वहां खाड़कू वे हैं जो आतंकवादियों से संबंध रखे हुए हैं और इसलिए संबंध रखे हैं कि उनकी आवश्यकताओं को आर्थिक पूर्ति नहीं होती है । नौजवानों को अगर हम अच्छा काम दे दें, उन्हें अच्छी तरह से रोजी रोटी दे दें, उनको सही रास्ते पर चलने का साधन दे दें तो वे खाड़कू नहीं बनेंगे । जब वे समझते हैं कि मरना ही है तो ठाठ से मरें । तय कर चुके हैं कि मरना है । एक और हम जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर हम जान दे देंगे । जितने दिन रहेंगे, लूट पाट मचा करके ऐश करेंगे । यह पंजाब की सबसे बड़ी समस्या है । मालूम हुआ है कि पंजाब के खाड़कूओं का संचालन करने वाली प्रमुख पंथिक कमेटी फौज की तैनाती पर चुप है और यह भी संभावना है कि खाड़कू संगठन फौज से गुरिल्ला युद्ध भी छेड़ सकता है । उनके पास न हथियारों की कमी है और न प्रशिक्षित लड़ने वालों की कमी है । समूची सिख और अकाली राजनीति एक स्वर से फौज की तैनाती का विरोध कर रही है ।

अभी बैंकों की बात कर रहे थे हंसपाल जी कि बैंक लूटे गये । ग्यारह करोड़ रुपये लूटे गये । न जाने कितने निर्दोष लोगों को मारा गया । बैंकिंग व्यवसाय वहां ठप्प पड़ा हुआ है । लेकिन डर उनको है जो उनके समर्थक हैं । सामान्य पंजाब की जनता को कोई डर नहीं है और पंजाब में केन्द्र सरकार द्वारा सेना की तैनाती को डेमोक्रेसी के रेस्टोरेशन का पहला कदम माना गया है क्योंकि वहां की पुलिस मिली हुई है, बराबर शुरू से ही सारे लोगों का कहना है, मैं नहीं कहता हूं । अधिकांश पुलिस के लोग मिले हुए हैं । आपके माध्यम से मैं माननीय गृह मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं पिछले रविवार को चंडीगढ़ में था । पंजाब के गवर्नर को मैंने फोन किया कि मैं मिलना चाहता हूं तो वहां गवर्नर हाऊस में किसी ने फोन नहीं उठाया । घंटी बजती रही कोई फोन उठाने को तैयार नहीं । मैंने पता लगाया कि पी०एस० कौन है . . . ।

तो पता लगा पी०एस० छुट्टी पर है । दूसरा, जो एक्टिंग पी०एस० है उसके घर मिलाया तो उसने कहा कि आप जा रहे हैं पंजाब, इसलिए आप संरक्षक तुल्य हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, उस पी०एस० ने कहा कि शायद आतंकवाद इतना है कि गवर्नर साहब कहां है, यह हम बताने में असमर्थ हैं । हमने कहा कि तुम्हारे गवर्नर साहब, मैं संसद् का सदस्य हूं, जब मैं बिल पास करूंगा तब यहां का बजट बनेगा, गवर्नर साहब तुम्हारे अगर डरपोक हैं तो पंजाब की समस्या क्या हल करेंगे ? जब मैं लौटने लगा तब उनका फोन गवर्नर के यहां से आया तो मैंने उसको रेफ्यूज कर दिया, क्योंकि संसद सदस्य की हैसियत किसी गवर्नर से तनिक भी कम नहीं है, वह पंजाब का गवर्नर हो या कहीं का भी गवर्नर हो । किसी भी दल के किसी संसद् सदस्य से मिलने के लिए उसे सम्मानपूर्वक, अगर आग्रह करता है तो मिलना चाहिए । हम कोई व्यक्तिगत काम कराने नहीं गए थे, बल्कि हम चाहते थे कि वहां की समस्या क्या है, उस पर बात करें और आ करके अपने सदन के नेता गृह मंत्री को बताएं कि यह चीजें हैं । इसको करिए । क्योंकि उसके सबऑर्डिनेशन में काम करते हैं सारी सच्चाई कहने में उनको भय होता जो वह अंडर काम करता है इस चीज को सीरियसली टेकअप करिए गृह मंत्री जी । जब डरपोक गवर्नर आपका होगा और उसके एक दिन पहले जैकब साहब गए थे, दूसरे दिन वह इतना डर गया कि मिलने को तैयार नहीं हैं । मैं मूल प्रश्न पर आ रहा हूं । राज्य और केन्द्र सरकार के उत्साह से जाहिर होता है कि पंजाब में चुनाव 15 फरवरी को हो जाएंगे । अकाली दल और सिख सियासी दलों को विश्वास में लेकर चुनाव की घोषणा चन्द्रशेखर जी ने की थी, हमने नहीं की थी और अब विरोध कर रहे हैं राजनीतिक दल के लोग । इतना ही नहीं, वामपंथी और कांग्रेसियों को विश्वास में लिया जा चुका है कि वह चाहते हैं कि चुनाव हों । अकालियों से कहते हैं आरोप जो लगाते हैं कि पूछा भी नहीं गया है अकाली दल श्री गुरचरण सिंह टोहरा अब उभर कर आए हैं, लेकिन खाड़कू उनको नहीं मानने को तैयार हैं । वहां से वह रिजैक्ट कर दिए गए हैं और वह हिट लिस्ट में हैं । जिनकी हत्या होनी है उनकी हिट लिस्ट

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

में गुरचरण सिंह टोहरा भी हैं और टोहरा के तेवर सरकार विरोधी भी हैं। यह भी पता लगा है कि हमारी सरकार पंजाब पैकेज की पूरी रूप-रेखा बना चुकी है और विरोधी दल के लोगों से बातें चल रही हैं। अगर नहीं चल रही हैं तो मैं समझता हूं कि आने वाले सप्ताहों में, संसद् रहते हुए, सब से बात, चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में प्रधान मंत्री, गृह मंत्री, जो उसका प्रोसैस होता होगा वह किया जाएगा, कैबिनेट बैठ करके बात करे और निर्णय करे। उनकी जो शंकाएं हैं, उनका हम लोग संसद् में समाधान न करें बल्कि उनको निरुत्तर करने का काम कैबिनेट का है, प्रधान मंत्री का है, गृह मंत्री का है, वह करें। पंजाब में शांति बहाल करने के लिए चंडीगढ़ को पंजाब को दिया जाए। चण्डीगढ़, लौंगोवाल से जो समझौता हुआ था वह पंजाब को देने की बात थी। मैं चण्डीगढ़ की बात कर रहा हूं। लेकिन जब पिछले दिनों हम सत्ता में नहीं थे तो वहां चंण्डीगढ़ में हम गए थे और अभी बैठे थे पार्लियामेंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर साहब भी, मेरे साथ गए थे और दस हजार लोगों की मीटिंग हुई जबकि वहां जाने में लोग कांपते हैं कि कहीं लाश न वापस आए, हम गए। वहां बड़ी जोरदार मांग उठी कि चण्डीगढ़ का यह जो रूप है, यही रूप रहने दिया जाए, उसकी यूनियन टैरिटरीशिप न खत्म की जाए। अभी पिछले शनिवार को परसों मैं चण्डीगढ़ में था और कई हजार लोग मुझ से मिले। उन्होंने यही कहा कि इस समय तुष्टिकरण की नीति हमारी सरकार को या किसी भी सरकार को त्यागनी होगी और अगर चण्डीगढ़ आप पंजाब को देंगे तो इधर हरियाणा में एक बवाल खड़ा होगा चण्डीगढ़ के लोग दुखी होंगे। दिल्ली किसी प्रांत की नहीं है, यूनियन टैरिटरी जो दिल्ली की है उसका अपना रूप है और चण्डीगढ़ को भी बड़े शान-शौकत के साथ बनवाया गया था। उतना सुन्दर बना हुआ दूसरा कोई नगर नहीं है उस पैटर्न पर, वहां तीन-तीन राजधानियां हैं। हमारी पंजाब की भी राजधानी है, चण्डीगढ़ की भी है और यूनियन टेरिटरी की भी राजधानी है। लाखों लोग रहते हैं और मैं चाहता हूं कि चुनाव के पूर्व आप एक विधिवत संसदीय कमेटी या एक्सपर्ट कमेटी बिठाएं और चुनाव के बीच में कोई ट्रांसफर करना एक तुष्टीकरण की नीति मैं मानता हूं, इसलिए चंडीगढ़ का रूप जो अभी है, उसको रखा जाय वहां तीन-तीन राजधानियां हैं, उन राजधानियों का स्वरूप एक अपना मौलिक रूप रखता है, एक विविध रूप रखता है, इसलिए उस रूप की सुरक्षा की जाए। इसकी मांग मैं सदन की ओर से सरकार से करता हूं। ...(**समय की घंटी**)...

उपसभाध्यक्ष (डा० नगेन सैकीया): पांच मिनिट में समाप्त कीजिए।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: मान्यवर, पंजाब में आतंकवाद से निपटने के लिए आपरेशन रक्षा दल (द्वितीय) बड़े पैमाने पर शुरू किया जा चुका है, लेकिन गृह मंत्रालय के पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि राज्य के प्रशासन, पुलिस और खुफिया सेवाओं का एक धड़ा आतंकवादियों के साथ मिलाए हुए है। गृह मंत्रालय के सूत्रों का यह कहना है कि अक्तूबर के मध्य में मण्ड क्षेत्र से पकड़े गए खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के तीन खाड़कुओं से की गयी पूछताछ से इस बात की पुष्टि हुई है कि सुरक्षा बलों का एक धड़ा जानबूझकर राज्य की खाड़कू गतिविधियों को नजरंदाज कर रहा है। पुलिस एवं खुफिया अधिकारियों ने गृह मंत्रालय को इस तरह की लिस्ट दी है जो खाड़कुओं की मदद कर रहे थे। अब जब वह लिस्ट आ गयी है गृह मंत्रालय के पास तो ये सब ऐसी चीजें हैं जोकि पब्लिक में नहीं कही जातीं, उन पर एक्शन हो रहा होगा और मैं कहता हूं कि कड़ाई से एक्शन होना चाहिए। ऐसे भी दस्तावेज मिले हैं जिनमें विभिन्न उग्रवादियों के बीच हुए पत्राचार और प्रशासन की ओर से गुप्त संदेश की पुष्टि होती है। काश्मीर के उग्रवादी संगठन हिज़बुल मुजाहदीन के कार्यकर्ता शकील अहमद के खालिस्तान कमांडो फोर्स के संचालक के नाम लिखे गए पत्र में पंजाब के दो अधिकारियों के नाम बताए गए

जिस पर गुरुदासपुर में गिरफ्तार घुस-पैठियों की रिहाई में मददगार होने का भरोसा किया गया है। पत्र में हथियारों की सही-सही क्वांटिटी और क्वालिटी बतायी गयी है। सुरक्षा बलों पर भारी राजनीतिक दबाव है। शिरोमणी प्रबंधक कमेटी के चुनाव के कुछ पहले एक उम्मीदवार के दबाव में पंजाब के विभिन्न इलाकों में बंदी कम-से-कम 10 उग्रवादियों को रिहा कर दिया गया है। एक अकाली राजनीतिज्ञ की दखलंदाजी से, एक ट्रांसपोर्टर जिस पर कि आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप था, उसे छोड़ दिया गया है। जून, 1991 में "टाडा" के तहत गिरफ्तार किए बहुत-से कैदी रिहा किए गए। उल्फा, हिजबुल मुजाहदीन, खालिस्तानी आतंकवादी और विभिन्न गैर-कानूनी संगठनों के बीच टैरेरिस्ट्स का पंजाब से संबंध स्थापित है और चुनाव स्थगित किए जाएं इसके लिए भी राजनीतिक दल के लोग दबाव डाल रहे हैं। मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि हमें पंजाब की समस्या हमेशा के लिए एक बार निपटा देनी है क्योंकि हमारे शहीद नेता राजीव गांधी जी ने वचन दिया था कि हम वहां डेमोक्रेसी को रिस्टोर करेंगे और पंजाब से आतंकवाद को मिटा देंगे। मान्यवर, इंदिरा जी ने अपने प्राण दिए ताकि खालिस्तान नहीं बनने पाए और राजीव गांधी अगर खाड़ी देशों के युद्ध के समय ...(**समय की घंटी**)... विदेश यात्रा पर न गए होते तो उनके प्राण न जाते, लेकिन वहां युद्ध रुक गया। ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब में भारत-पाक सीमा पर स्मगलिंग होती है। अभी बताया गया कि वहां हैरोइन से ले कर सोना तक आता है, ऐसी स्थिति में देश के जितने स्मगलर्स हैं और नंबर दो का धंधा करने वाले हैं, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय चव्हाण साहब से कहना चाहता हूं कि अब वह समय आ गया है जब उन पर हाथ डाला जाय और जो ब्लैक मनी है उसको निकाला जाय। यह ब्लैक मनी ही सारे आतंकवाद के पीछे है और उसके माध्यम से विदेशी ताकतें हथियार से लेकर इंसानी ताकत तक को खरीद रही हैं। इसलिए उसे समाप्त करने की जरूरत है...(**समय की घंटी**)...वहां जगह-जगह पर संपर्क समितियां बनाने की जरूरत है। मान्यवर, वहां के नागरिकों में उत्साह है। मैं इधर कई बार गया हूं...(**व्यवधान**)... संपर्क समितियां बनाई जाएं और जो तत्व है, जो पंजाब छोड़कर भाग रहे खाड़कू आतंकवादी देश में फैल रहे हैं, उनका पता लगना चाहिए और वे वहीं हों—"क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसमें धरा गरल हो, उसको क्या जो दंत-हीन विष रहित विनीत सरल हो", जो जहर भरे हुए ये नाग हमारे देश को डंसने के लिए चल रहे हैं और राजनीतिक दल के लोग उनमें आग लगाने का काम कर रहे हैं, इनको देखना होगा। इस देश में सरदार लोग, सिख लोग हमारी वीर कौम पंजाब की है। क्या आपके दल शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं हैं और आपके शिव सेना के चीफ ने यह नहीं कहा कि इस देश में कोई सिख तब तक रह सकता है जब तक वह क्लीन शेव हो और साफा न बांधे होगें आखिर क्या है, आप कराना क्या चाहते हैं ...(**समय की घंटी**)... पंजाब का हम चुनाव करने जा रहे हैं।

यहां कच्छा, कड़ा, कृपाण, कंघी, केश यह पांच सत्कार हैं, जिसे सिखों ने ही नहीं पूजा है, हिंदुओं ने नहीं पूजा, सनातन धर्म ने पूजा, सारे देश ने पूजा है। मान्यवर, सदन के अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति जी एक पुरस्कार वितरण समारोह में जब पुरस्कार बांट रहे थे तो उस समय गृह मंत्री जी भी उपस्थित थे, इंदिरा गांधी अवार्ड फिशियल लैंगुएज अवार्ड था। आपको स्मरण होगा गृहमंत्री को, कि उन्होंने कहा था कि पंजाबी के 35 प्रतिशत शब्द संस्कृत से हैं। देश को जोड़कर हम समस्त भाषाओं का निर्माण कर रहे हैं, समस्त जातियों का निर्माण कर रहे हैं और सुपर पावर के इशारे पर आप उनके गुलाम बना करके इस देश को तोड़ना चाहते हैं यह नहीं होगा।

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं विश्वास करता हूं कि पंजाब में होने वाला चुनाव इस बात का सबूत होगा कि हमारे स्वर्गीय नेता राजीव गांधी ने जो कुछ कहा था, उसकी पूर्ति नरसिंहराव जी की सरकार कर रही है और वह दिन आएगा,.....

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): If you continue, nothing will go on record.

डा० रत्नाकर पाण्डेय: जब पंजाब में पूर्ण शांति होगी। धन्यवाद।

श्री महेन्द्र सिंह लाठर (हरियाणा): वाइस चेयरमैन सर, मुझे खुशी है कि होम-मिनिस्टर साहब यहां पर इस हाऊस में बैठे हैं। क्योंकि मैं समझता हूं कि जो डिसकशन अब तक की होती रही है या जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं, इन बातों का ज्यादा संबंध फाइनेन्स मिनिस्टरी से न होकर होम-मिनिस्टरी के साथ है।

वाइस चेयरमैन सर, वैसे तो किसी भी प्रांत का बजट पास करना, खर्जा पास करना पार्लियामेंट का काम नहीं है, लेकिन पंजाब के हालात को देखते हुए; वहां पर राष्ट्रपति शासन को देखते हुए यह कंस्टीट्यूशनली ड्यूटी हमें हरसाल अंजाम देनी पड़ती है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि इलैक्शन के बाद भी वहां पर कोई सरकार रहने वाली नहीं है, हमें यह काम जारी रखना पड़ेगा।

वाइस चेयरमैन सर, पंजाब जो भारत देश का एक नंबर का प्रांत है, जो सारे देश को अनाज पैदा करके खिलाता है, जो फौज में भरती होने के लिए बेहतरीन नौजवान भेजता है, जो पंजाब भांगड़े के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए मशहूर है वह पंजाब जहां दूध और मक्खन की नदियां बहती थीं, आज उस पंजाब की यह दुर्दशा है कि वह देश के लिए एक नासूर बन गया है, एक अभिशाप बन गया है। इसके लिए जिम्मेवार इस देश के सभी लोग हैं, सभी शासी लोग हैं खासतौर पर। लेकिन, मैं समझता हूं कि यह सबसे बड़ी देन कांग्रेस पार्टी की है।

वाइस चेयरमैन सर, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पोलिटिकल ताकत वहां पर गेन करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने संत भिंडरावाला को पैदा किया। संत भिंडरावाला का पहले कोई नाम नहीं जानता था। उसको ताकत दी और ताकत भी उसको इतनी दी कि कोई कानून उस पर लागू नहीं होता था। मुझे याद है, मैं करनाल का रहने वाला हूं, वहां पर जब संत भिंडरावाला जी आए। वैसे अगर किसी के पास एक बरछा या भाला हो या जिसके पास छह इंच से फालतू लंबा ऐसा शस्त्र हो तो उसे आर्मज एक्ट के तहत पकड़ लिया जाता है यानी आप लेकर चल नहीं सकते और बिना लाइसेंस रिवाल्वर या पिस्टल तो आप रख नहीं सकते।..... लेकिन जब संत भिंडरावाला अमृतसर से चले तो उसके साथ जो भरी हुई बस थी, उसके अंदर आटोमैटिक व्हीपन्स की नुमाइश करते हुए लोग थे और किसी के पास कोई लाइसेंस नहीं था। वे हमारे करनाल में भी रुके और वाइस चेयरमैन साहब, वे अमृतसर से चलकर मुंबई तक गए। कांग्रेस की सरकारों ने, सैंटर में भी उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, उसको किसी ने नहीं रोका-टोका क्योंकि अकाली पार्टी को खत्म करने के लिए एक जोहरा कांग्रेस पार्टी ने चुना था। पंजाब के अंदर अकाली पालिटिक्स एक बहुत इम्पोर्टेंट पालिटिक्स थी, उनको खत्म करने के लिए, अकालियों को, भिंडरावाला को पैदा किया। लेकिन जब सही मायनों में भिंडरावाला ताकतवर हो गए, उस वक्त ब्लू स्टार आपरेशन करके उसको मरवाया गया। वाइस चेयरमैन साहब, यह सिख कौम, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसे मैं बहुत बहादुर और मेहनती कौम मानता हूं, उन्होंने उसमें हरमन्दिर साहब की बेइज्जती की और तभी से उनके अंदर यह भावना पैदा हुई कि क्या हम इस देश में बिना एक अलग स्टेट मांगे रह सकते हैं मे उसके

बाद श्रीमती इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ, उसको चारों तरफ से कंडेम किया गया, कोई भी इस किस्म की हत्या हो तो उसको कंडेम किया जाना चाहिए । लेकिन उसके बाद क्या हुआ ? श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या का बदला बेगुनाह सिखों से लिया गया और उपसभाध्यक्ष महोदय, बेगुनाह सिखों के गले में टायर और तेल डालकर जलाया गया, हिमाचल प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर, कानपुर के अंदर। आज कांग्रेस पार्टी के लोग, रत्नाकर पाण्डेय जी भी बहुत जोर लगाकर सिखों की तारीफ कर रहे हैं। क्या उन लोगों को, जिन्होंने यह कत्लेआम किया, क्या आपने किसी एक भी आदमी को सजा दिलाई है? क्या आज भी वे खुलेआम नहीं फिरते हैं मैं क्या आज भी वे गवर्नमेंट के अंदर नहीं बने बैठे हैं? उपसभाध्यक्ष महोदय, सिखों की कौम एक खुद्दार कौम है और अगर उनकी खुद्दारी को कोई ठेस पहुंचती है तो वे उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि चन्द्रशेखर जी ने थोड़े दिनों के अंदर यह कोशिश की थी कि जो भाई भटक गए हैं, रास्ते से हट गए हैं, उनके साथ बात-चीत करके कोई हल निकालें, इलेक्शन का ऐलान किया लेकिन इस सरकार ने आते ही सबसे पहला काम इलेक्शन को पोस्टपोन करने का किया, जिसकी कोई वजह नहीं थी। यह सब पालिटिक्स थी। अब भी जो कांग्रेस वाले लोग कर रहे हैं वहां पर, वहां से कुछ सीटें हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार की ढुल-मुल पालिसी की वजह से यह पंजाब की प्राब्लम बनी । जब हरियाणा बना उस समय शाह कमीशन एप्वांइट हुआ । जो उसकी रिकमेंडेशन्स थी, गवर्नमेंट का फर्ज बनता था उसको सेंट-पर-सेंट रिकमेंडेशन्स को लागू करना चाहिए था, जिसके तहत चंडीगढ़ हरियाणा को दिया गया था, लेकिन वहां की पालिटिक्स के प्रेशर में आकर उन्होंने शाह कमीशन की रिकमेंडेशन्स नहीं मानी और अपना अवार्ड—इंदिरा गांधी अवार्ड, जिसमें कहा गया कि चंडीगढ़ हम पंजाब को देंगे और उसके बदले में आबोहर, फाजल्का, 107 गांव और नई कैपिटल बनाने का सारा खर्चा सरकार देगी । यह दूसरा अवार्ड था । वह उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थीं, मालिक थीं देश की, लेकिन वह इंदिरा अवार्ड कहां है ? क्या कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस सरकार ने उसको लागू किया ? उसके बाद मैं बताता हूं उपसभाध्यक्ष महोदय, कि किस किस्म की ढुल-मुल पालिसी इन डिसिजन्स की और यह जो Non-implementation of the decisions taken by the Government—एस०वाई०एल० के पानी का फैसला हुआ, बंटवारा हुआ । यह पानी पाकिस्तान से खरीदा गया था ताकि जो हरियाणा और राजस्थान की सूखी जमीन थी वहां पर इस पानी को दिया जाए । उसका बंटवारा किया गया, साढ़े तीन हमारे हिस्से में आया था हरियाणा के । उसके लिए हमने नहर बनाई करोड़ों रुपए लगाकर लेकिन वह पानी हमें आज तक नहीं मिला । जब चन्द्रशेखर जी की सरकार थी, उन्होंने फैसला किया कि बार्डर कंस्ट्रक्शन फोर्स के हवाले किया जाता है, वह बनाएंगे, वहां की सरकार नहीं बना सकती, पंजाब की । मैं मीटिंग में शामिल हुआ था, जब शुक्ला जी यने मीटिंग ली थी और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भजन लाल जी भी उसमें शामिल थे और राजस्थान और हरियाणा के सारे एम०पी० शामिल थे, उसमें उन्होंने ऐलान किया कि यह फैसला सरकार ने कर लिया है कि बार्डर कंस्ट्रक्शन फोर्स के हाथ में हम यह काम दें देंगे । लेकिन जब इलेक्शन का फैसला करने के बाद यहां पर सवाल पूछा गया शुक्ला जी से, तब उन्होंने कहा कि हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है । यहां पर सवाल पूछा गया शुक्ल जी से, तब उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है और एक्स०वाई०एल० कैनाल के कंस्ट्रक्शन का जो काम है वह पजाब गवर्नमेंट फैसला करेगी कि कौन सी एजेंसी बनाये । अब पोजिशन बदल गयी । कोई फैसला करना नहीं चाहता और अगर कोई फैसला करते हैं तो उसको लागू करना नहीं चाहते ।

सर, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जो हालात आज पंजाब के अंदर हो

[श्री महेन्द्र सिंह लाठर]

रही है, इसको हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिये । हंसपाल जी ने एक बात कही कि बीमारी बहुत बड़ी है, पुरानी बीमारी है । इसका इलाज एक-दो दवाई देने से नहीं होता । बाकी स्टेट्स के अन्दर भी बेचैनी फैल रही है । वाईस चेयरमैन साहब, मैं तो अपनी तरफ से पूरे जोर से यह कहना चाहूंगा कि जो सिस्टम आफ गवर्नेन्स हमने अपनाया था, जो विधान हमने लिखा था वह आउट-डेटिड हो चुका है ।

इससे बड़ा और क्या सबूत है कि हमारे कंस्टीट्यूशन के साथ 60 दफे खिलवाड़ की जा चुकी है, अमेंडमेंट की जा चुकी है । हमें इस विधान के ऊपर, उस सिस्टम के ऊपर नजरसानी करनी पड़ेगी, एक सेकिंड लुक देना पड़ेगा । उसके लिये चाहे एक्सपर्ट कमेटी बनायें, चाहे आप कंस्टीट्यूयंट असेंबली बनायें । यह सारे सिस्टम का गौर करने के लिये, स्टेट्स के अंदर जो बेचैनी है, आज है क्या ? ...(घंटी)... जो भी काम होता है सैंटर से होता है । वाईस चेयरमैन सर, सैंटर का इंटरफियरेंस इन सेवरी स्टेट, जिस स्टेट की गवर्नमेंट सैंटर के मुताबिक काम नहीं करती है उसको डिसमिस कर देते हैं, प्रेजीडेंस रूल लागू कर देते हैं । फाइनेंशियल मैटर्स में हर स्टेट को सैंटर की तरफ देखना पड़ता है । बाढ़ आती है, नुकसान होता है तब सैंटर की तरफ हाथ फैलाते हैं । यह सिस्टम चलने वाला नहीं है । अगर आपको देश को एक रखना है, अगर इस देश को अखंडता रखनी है तो आपको इस के ऊपर दोबारा गौर करना पड़ेगा । जितने हमारे प्रांत हैं, अलग-अलग भाषाएं हैं, अलग-अलग रिवाज हैं, अलग-अलग रहन-सहन हैं वह अपने तरीके से पनपना चाहते हैं, अपने तरीके से अपने आपको डवलप करना चाहते हैं । हमें क्या ऐतराज है अगर हम स्टेट्स को और ज्यादा पॉवर दें ? जैसे आपका डिफेंस है, आपका फायनेंस है, आपका फारेन एफेयर्स है या इस किस्म के जो इंपोर्टेन्ट सब्जेक्ट्स हैं उन सबको सैंटर अपने पास रख सकती है, लेकिन स्टेट को ज्यादा पॉवर देनी पड़ेगी, ताकि वह अपने ढंग से, अपने सिस्टम से, अलग कानून बनाकर के, अपने तरीके से चला सके । तो मेरा यह सुझाव है । मैं सीरियसली इस सुझाव को दे रहा हूं कि हमें अपने इस सिस्टम को और अपने कंस्टीट्यूशन पर दोबारा से नजर डालनी पड़ेगी । ...(समय की घंटी)... वाईस चेयरमैन सर, दो मिनट और लूंगा ।

कोई भी स्टेट का जो मामला होता है, आपस में दो स्टेट का जब झगड़ा होता है तो दोनों स्टेट के रिप्रजेंटेटिव को कांफिडेंस में लिया जाता है । लेकिन वाईस चेयरमैन साहब, मुझे बड़ा अफसोस है कि जब हमारा, पंजाब का जब भी कोई मामला आता है तो हरियाणा के लोगों को कभी विश्वास में नहीं लिया जाता । राजीव-लौंगोवाल एकार्ड हुआ, उसके अंदर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को, किसी मिनिस्टर को, किसी लीडर को नहीं पूछा गया, एक तरफा फैसला उन्होंने सुना दिया और इंदिरा गांधी एवार्ड को खत्मकर दिया । मैं समझता हूं, जो अब भी पैकेज प्रोग्राम की बातचीत चल रही है, मैं होम मिनिस्टर के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि आज अगर कोई भी फैसला करते हैं जिसका असर हमारे हरियाणा के ऊपर भी पड़ता है तो उसके लिये आपको हरियाणा के सारे लीडर्स को, हरियाणा कॉ सरकार को कांफिडेंस में लेकर कोई फैसला करना चाहिये । तो सुनने में आता है हरीकिसन सुरजीत सिंह जी ने कह दिया कि यह तो पैकेज प्रोग्राम में चंडीगढ़ पंजाब को दिया जा रहा है । हरियाणा के लोग इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे । होम मिनिस्टर सर । हरियाणा के लोग चंडीगढ़ देने के लिये तैयार हैं, बशर्ते कि उनको अबोहर, फाजिल्का और 7 गांव हरियाणा को दिये जायें और पैसा दिया जाय जिससे कि हम अपनी केपिटल बना लें । The people of Haryana must not to be taken for granted. हम किसी बेजा बात को, किसी नाजायज बात को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे । हम नहीं चाहते कि पंजाब का यह फैसला लटका रहे ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Now please conclude.

श्री महेन्द्र सिंह लाठर : वाईस चेयरमैन सर, दो-तीन मिनट और लूंगा ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): The time allotted to you is only 7 minutes which you have already covered. Now, pleased conclude. I am giving you one more minute to conclude. Otherwise, nothing will go on record.

श्री महेन्द्र सिंह लाठर : वाईस चेयरमैन सर मैं यह सब्मिट करना चाह रहा था, हम भी चाहते हैं कि पंजाब का मसला हल हो, उसके लिये तो मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि वहां जितने भी अनएम्प्लाईड युथ हैं उन सबको नौकरी दी जाये । आप चाहे उनको फौज में भर्ती करें, चाहे उनको पुलिस में भर्ती करो । आप चाहे उनको फौज में भर्ती करें, चाहे आप उनको पुलिस में भर्ती करें, चाहे उनको बड़-बड़ कारखानों में भर्ती करें, वहां का जो युथ है, उसको बरगलाया जा रहा है ।

महोदय, मैं पाकिस्तान के फैक्टर की बात कहना चाहता हूं । हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, एम्बेसडर लेबल की मीटिंग्ज हो रही हैं, सैक्रेटरी लेबल की मीटिंग्ज हो रही हैं पाकिस्तान के साथ । हमने बड़े एतराज किए हैं पाकिस्तान के साथ और हमने इस मसले को उठाया है। हमारे होम मिनस्टर साहब ने कहा कि हमारे पास सबूत हैं कि पाकिस्तान दखल दे रहा है । वह समझता है कि हमने उसके मुल्क के टुकड़े किए थे, तो वह हमारे मुल्क के टुकड़े करना चाहता है ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Dr. G. Vijaya Mohan Reddy.

श्री महेन्द्र सिंह लाठर : महोदय, इससे हमें मदद मिलने वाली नहीं है ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Now if you don't conclude, nothing will go on record.

श्री महेन्द्र सिंह लाठर : वाईस चेयरमैन सर, मैं सुझाव दे रहा हूं एक मिनट के लिए ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): No, you can't go on speaking in this way.

श्री महेन्द्र सिंह लाठर : मैं सरकार को सुझाव दे रहा हूं कि पाकिस्तान के साथ नरमी की जो पालिसी है, वह हमें छोड़नी पड़ेगी... (व्यवधान) चाहे हथियार उठाने पड़ें, चाहे कुछ करना पड़े, हमें अपने देश की एकता की... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Dr. G. Vijaya Mohan Reddy. His speech is not going on record.

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, the Punjab question is a national question. Nothing in this world is static: everything is changing. That's why, the consensus which the Congress Party wants to arrive at after discussion is a very welcome sign and I hope the Congress Party will succeed in holding elections on February 15 as promised on the floor of the House.

Sir, our country is a democratic country with a tradition of democracy for thousands of years. It has been a beacon to the whole world and we must succeed.

The Corporation elections which were held in Punjab, if they are any sign, have shown that the people are very much interested in elections. They do not want this bureaucratic type of rule which is corrupt and anti-people. That itself shows that the people of Punjab are for elections.

Now my friend was telling about Pakistan. We must be very much alive to the situation. Pakistan, in spite of so many changes that have come about in the world, persists in its policy of arrogance and, especially, belligerence to our country. They are training terrorists—call them Khalistani militants, Kashmiri militants or by any other name—and sending them here. Not only that. According to the press, not a day passes

[Dr. G. Vijaya Mohan Reddy]

without unprovoked firing on our borders so as to protect and give cover to these militants who art entering our country. Not only that. They want to link up the Punjab and Kashmir militants, have a common plan, and they are succeeding to some extent. That has also come in the press. Not only that. Even today there is a report in the press that a clandestine radio is being operated with very venomous propaganda against our country which is reaching our border districts, and thus they are trying to disturb the conditions in those areas. This also has to be taken care of because on the propaganda front, I feel, we are very weak.

It is a good sign that the United Kingdom and the United States as our Home Minister has stated, through their agencies, would check the flow of funds to terrorists from outside India. It is good but they should take a firmer stand. If they want to really help in the situation, they must, impose sanctions against Pakistan. Then only the situation can improve. And we must impress upon those Governments that their simple soothing words are not going to help and they must come out with stricter measures against Pakistan.

Then, the militants are acting according to a plan. The day before yesterday we have seen it in the press now that things have become hot in Punjab, they entered Haryana and indulged in a carnage, massacring tens of persons. So also in the Terrai districts of Uttar Pradesh. Now they are having a kind of a plan so that they can sneak into other States and to see that their activities are alive. Therefore, this has to be taken note of, and we must curb these activities. The blood of innocent people has been flowing.

The small-scale industries they want to disturb. So also other industries. Punjab is a hub of i dustry. Its cities are hubs of i dustries. But they are getting di turbed. Some persons are sellir their shops and coming out. So al industrialists are trying to come o of Punjab. These industries a employing about a million people. that is disturbed, the terrorist act vities are allowed to go on, then, becomes very difficult for us. The will succeed in their plan of divid communal divide which they are a tempting to create. That is why, this connection also we want the M nistries to get into discussion an see that this type of situation do not continue to exist, in which t economic activity is affected.

It is to the credit of Punjab, th people of Punjab that inspite of a these happenings, Punjab remain the Punjabi people remain a part o our culture, a part of our countr and they are firm defenders of th integrity of our country. There h not been one communal incident i Punjab. The agricultural productio in the rural areas is keeping to th target; 120 lakh tonnes of paddy the have produced this year also; 65 lak tonnes of wheat they have produce So also, they have improved the pr duction of cotton, improved the pr duction of sugarcane. The indust rial production is keeping pace wit the general progress that is bein made.

These are positive signs which ar there. The Government of Indi should exploit them, get into touc with all the sections of the peopl who are fighting back vigorously an try to see that they stand on thei own legs and that their hearths an homes are defended.

About the administration, so man remarks have come in. This typ of thing we saw when we were fight ing against the Nizam, what is mean by this police terror and their third degree methods, innocent people be ing arrested. That Punjab problem always happens whenever such a

kind of action takes place. This Punjab problem has been going on for a decade. That is why it has been ingrained in the police force. This type of terror is being created. It is linked up with corruption also. This has to be taken note of. All those officers who are involved in these activities should be sent out of the administration. When Mr. Jacob visited Chandigarh, he also received several reports that inspite of the huge sacrifices made by the people, these fake encounters, extortions of money, repression by the security forces goes on. Unless this is curbed by a firm hand, the situation will not improve. That is the opinion that has been given to Mr. Jacob. Even the Congress Party representatives have told him that key officers in the disturbed areas must be removed so that there can be a better administration there. There should be more coordination. When the army is there, there must be good coordination among the armed forces, the civilian government and the police also. This has to be attempted. From the grass-roots level to the highest level there should be perfect coordination.

I am of the opinion that there should be a package. It has come in the Press that a package is being formulated, that a 22-point formula is being formulated. So many things are coming in the Press. Because it is a promise of the nation. it should be a promise of the nation to the people of the Punjab. For that sake, whatever it is, it should be announced from the floor of the House. An economic package has been announced. So also it should be announced about the river waters dispute that it will be referred to the Supreme Court. So also the question of Chandigarh. Whatever it may be, you must discuss with political parties. Firmly you must be in a position to come out with a statement on the floor of the House itself so that it becomes the nation's promise to Punjab. This is the Government has to understand.

Election promises are not going to help any more. Even parties which make election promises cannot benefit from them. Nobody would believe them because in Kashmir you promised Rs. 1,000 crores. Where is Rs. 1,000 crores? Were we able to give it? Our promises must be sincere. We must be in a position to fulfil those promises.

About the Centre-State relations, I want to say that unless the Centre parts with its powers and gives them to the States, it will become difficult for the States to understand that a federal set-up is functioning and that they can carry on their economic and political activities with freedom. This has been represented by all the Ministers and Chief Ministers at the Inter-State Council meeting irrespective of the parties to which they belonged. Now, the Sarkaria Commission is being discussed , but you must be in a position to come out with some results out of those discussions immediately. Not only that, all those powers which you have taken away from the State must be given back to them. You have taken away financial powers, political powers and administrative powers. You must give them back to the States. Merely keeping 80 per cent of the revenue will not improve matters. States cannot live on doles or grants from the Centre. Their planning process must be strengthen and all the promises in regard to the federal set-up, economic package, and political package should be met to strengthen the popular movement of Punjab to assert its personality. All parties are prepared to cooperate with the Government. There is no question of not cooperating. No Indian is outside the

[Dr. G. Vijaya Mohan Reddy]

ambit of action in Punjab. That is why I say, you pleast go ahead with confidence. Let there be election on the 15th and the next Budget be passed by the Punjab Assembly and let peace prevail there.

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA (Punjab): For tne last five and a half years I have been trying to promote that there should be elections in Punjab. Therefore, I am happy that the present Government after five months have come to a decision that there will be an election in Punjab. But the question is can just the announcement that elections will be held and that the police and military have been deployed to hold those elections and to control violence provide an answer? Is it a law and order problem only or has this Punjab problem certain other vital aspects? Just to say that you are going to hold elections and take no notice of other vital aspects means that you are putting the cart before the horse or you are going to have elections at great expense and at great effort in spite of certain amount of violence which is bound to occur and not glean the results that should come from it.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Mr. Aurora, just one minute. With the permission of the House I would request Shri Jagesh Desai to occupy the Chair for a few minutes.

[The Vice-Chairman (Shri Jagesh Desai) in the Chair]

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: Mr. Vice-Chairman, Sir, I was mentioning about holding an election without making any effort to clear the atmosphere about the basic questions which have actually originated this problem. I am not going into the history as to who is responsible and who is not. but I cannot help saying that there are certain steps that were taken by the Centre when the Government was being run by the Congress Party that have caused tremendous amount of spirit of revenge, a great deal of pain and also a great deal of erosion of credibility as far as Punjabis generally and Sikhs particularly are concerned. Definite efforts were made to 5.00 P.M. destroy the Akali party. The Akali party which had been agitating for the Sikh rights, for a unilingual State for Punjabis, for having Chandigarh. All these efforts were carried out the agitation was carried out totally peacefully till Bhindranwale factor came in for which the Congress party was responsible. Therefore, the violence was instigated by the Congress through Mr. Bhindranwale. You have to accept that. Now you have got to realise that this violence cannot be done away with, cannot be overcome by State repression by police and military methods. However, this violence can eventually be won over by winning the hearts of those people who have been hurt, in whom a rising spirit of revenge has resulted that it is no use fighting a peaceful agitation. They have taken to the gun and violence.

Therefore, my request is that the Government should clarify its position on certain things that took place in November, 1984 to the people of Punjab. What is going to be your attitude towards these happenings? The first thing that hurt the Sikh psyche terribly is the violence in Delhi and elsewhere in November, 1984. Not a single wrong-doer or the quality has been punished so far. The present Government's policy continues to be what it was during the previous regime. Protecting the wrong-doers Protecting the guilty is something which will continue the schism that has taken place between the Congress and the Sikhs.

The next point I would like to make is, please do remember that the Sikhs had been given certain promises even before 1947. Don't ignore

them. You have promised them a place somewhere in India where they can feel " the glow of freedom". Now you turn around and say "What is meant by this glow of freedom?" I would like to explain this. The Sikh community are very conscious about their identity. They are also conscious about the threat to their identity. What has been happening is that the Congress has always tried to look for a "poodle" or Mary's little lamb as the leader from the Sikh community. If they did not find one they tried to create one. This has been an extremely wrong policy which you were following. They tried to create a leader that is acceptable to them and who can win the elections and not who is acceptable to people not you. This policy must change. Therefore, hold the elections. The people of Punjab and the Sikhs want to know what is in your mind especially about the future of Punjab. I am sure that the Sikhs will join the elections. All the moderate elements and may be quite a few of the so-called militants will join the elections. But with the present lack of credibility there is a chance that the Sikhs will be compelled not to join the elections. Then, it will really be a tragedy. My worthy friend, Mr. Hanspal has brought out that if the elections are held without the Sikhs' participation, it would be no elections. Please do remembers that the Congress party was in power in Punjab but they found it difficult to run the administration. Eventually, President's rule had to be imposed in 1983. I do not want to mention any name. But that is so. Therefore, if you are going to have elections, please do take these necessary steps. The steps I suggest are as follows First thing is, establish your sincerity. And that can be done. The second point is, give an idea of the future shape and with that, you have to at least give the Punjabi farmer confidence that the Punjab waters, the waters of Punjab rivers will not be denied to him for his needs and may be given away to some other areas. I am not saying that all the river waters must be given to Punjab. But their needs must have priority. And that assurance can be easily affected if the Punjab river water problem is sent back to the Supreme Court. Let them decide it rather than bringing in politics into it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Please conclude now.

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: I will have to take two or three minutes more. I am sorry about it. But I think this a very rare chance I get once in six months. I am hoping, very sincerely hoping, that I will not have to make use of it next time.

The third thing is Chandigarh. I know that there are people living in Chandigarh who do not want Chandigarh to go to Punjab but remain as a Union Territory. On the other hand, if Chandigarh is now denied to Punjab, which had been promised in the Longowal-Rajiv Accord, it will again mean the same thing, another agitation I am sure you do not want to have further agitations after this election. You really want to get together and find answers and arrive at a really practical solution.

The fourth thing that I have—which, I think, has been expressed by other members also—is, have a good look at the Anandpur Sahib resolution with regard to the State-Centre relationship. In fact, the Sarkaria Commission is being discussed. I know that. The Sarkaria Commission has not gone far enough. It is now outdated already. And Anandpur Sahib resolution, signed by Sant Longowal, is the document that you have to study and see how it can be applied, not only to Punjab but to all the States.

[Sardar Jagjit Singh Aurora]

I would like to make one final point and that is about the attack on the Golden Temple. It has caused to the Sikh psyche a tremendous injury. No regret has ever been expressed. There was the killing of thousands of people in Delhi and elsewhere. No regret has ever been expressed, either on the floor of the House or anywhere else. If you want the Sikhs to remain as a part of the mainstream—and before 1984, they never felt that they were not a part of the maintream—you have to do something about it. Do not stand on prestige. Admitting your fault is a sign of greatness; not being able to do so normally causes greater harm and greater injury.

[The Vice-Chairman (Shri Bhaskar Annaji Masodkar) in the Chair]

To end up, this is an opportunity I hope you will not miss. In this opportunity, please make all efforts toget the Sikhs join the elections. And to do that be bold, be courageous and take such decisions that will give you good dividends.

Thank you very much.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: (West Bengal): Sir, the Punjab problem only reflects the colossal failure of the Indian politics. The nation is paying for the stupidity and the follies that the previous political leaderships, one after another, had committed. I have no hesitation in saying, Sir, that even after six years of Presidential rule we are where we had been. It is almost a mini-emergency because the number of armed personnel there in terms of the population, if you count it comes to one security personnel for every fifteen civilians in Punjab. Even after deploying such a huge force—military, paramilitary, and police— we have not been able to bring about a change in the situation. This is because of the fact that the political forces who are opposed to terrorism have not combined together to bring about a change in the equation of the political forces. That is another aspect of the failure of the situation. Those parties who believe that terrorism should end and democratic life should take its course have not been able to combine together to make a united effort to restore democracy in Punjab. That is the second failure. Therefore, there can be no alternative but to face election and whoever may be voted to power, whatever may be their political complexion, it is the people and their elected representatives who should be brought back to office and let us not believe that the Government of India should act as the guardians of the people of Punjab. Nobody needs any guardian over and above their elected representatives. Our attitude should totally change. There should be 180 degree change in the policy of the political parties and political life of the country. We should face the people; elections should be held and whoever forms the Government should be allowed to do so. But again we know that there are certain limitations. The Government that is formed, will have to function within the limits of the Indian Constitution. That is the only safeguard and keeping that safeguard in view, we should go to the poll. There should not be any pre-condition that by deploying the army or paramilitary forces, we will be able to clear the garbage, we will be able to free Punjab from terrorists and after freeing Punjab from terrorism, we shall hold the elections. That is a total Utopia. We had believed in Utopia and the nation had paid for it. Now it is time for us to go to the elections and I believe that all the political forces who are opposed to terrorism shall find it necessary to combine together to face the challenge and restore democracy in Punjab.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Now hon. Members, there is a

statement to be made by the Minister of State for Railways with regard to the accident. So we will request the Minister to make a statement.

(*Interruptions*).

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Sir, there are only two or three speakers left. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): No, there are five speakers.

STATEMENT BY MINISTER

Train accident to 3 Pathankot-Baijnath Passenger rain between Jawanwala Shahr-Harsar Dehri on Pathankot—Joginder Nagar Narrow Gauge Section of Northern Railway on 712-1991.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): Sir, It is with deep anguish that I apprise the House of the tragic accident to train No. 3 Pathankot-Baijnath Passenger at about 15.00 hours on 7-12-91 on the Pathankot-Joginder Nagar narrow gauge single line section of the Firozpur Division of Northern Railway. While this train with 6 coaches was on run between Jawanwala Shahr and Harsar Dehri stations, 2 coaches next to the train engine derailed and capsized at Km. 47/7-8. As a result of this derailment, 27 persons lost their lives and 73 passengers sustained injuries.

Immediately on receipt of information about the accident the medical relief van with Divisional Officers and doctors were rushed to the accident site from Pathankot. The Divisional Railway Manager/Firozpur also left for the site of the accident to supervise relief operations. Local Civil and Police Officials also attended the acident spot. The injured were admitted to the civil and military hospitals at Nurpur, Jawanwala Shahr and Pathankot. Military personnel also assisted in attending to injured passengers.

The Member Engineering, Railway Board along with General Manager, Northern Railway and Senior Officers also proceeded to the site of accident to oversee rescue and relief arangements.

I proceeded by special airforce plane along with Member Traffic to the site of accident. I visited the ijnrued in the hospitals and also inspected the accident site.

Ex-gratia payment to the next of kin of the dead and to the injured is being arranged.

The Commissioner of Railway Safety, Northern Circle, will be holding a statutory inquiry into this accident from 10.12.1991.

I am painfully conscious of the public misgivings about rail safety that are provoked by such unfortunate accidents. Every single accident is a matter of serious concern to me and all Railwaymen as it is to the general public. While I assure the House that the officials guilty of causing this accident through their negligence, will be severely punished, I crave your indulgence to view Railway performance in the proper perspective.

Indian Railways operate about 14,000 trains a day with a workforce of 1.6 million Railwaymen working round the clock in diverse conditions and with equipment of varying complexity. The failure of a single human or mechanical component of this gigantic network can cause an accident. This is the magnitude of the challenge confronting the Indian Railways.

In view of the recent criticism about Rail safety, I think it is necessary to quote certain key statistics